कंचन उजाला

हिन्दी दैनिक

RNI No : UPHIN/2019/79194

कंचन उजाला

लखनऊ से प्रकाशित | सच्चाई के साथ...

WWW.Kanchanujala.in | Kanchanujalalko@gmail.com

वर्ष : 05 अंक: 74 | लखनऊ, शुक्रवार 01 मार्च 2024 | मूल्य- एक रूपया | पृष्ठ - 6

जल्द ही तहसील स्तर पर फायर स्टेशन वाला पहला राज्य होगा उत्तर प्रदेश: योगी

संवाददाता

लखनऊ। संकट के समय अग्निशमन सेवाओं की भूमिका से सभी भलीभांति परिचित हैं। इसी को ध्यान में रखकर वर्ष 1944 में प्रदेश में विभाग का गठन किया गया। वर्ष 1944 से 2017 के बीच 73 वर्षों में केवल 288 फायर स्टेशन स्थापित किये गये जबकि पिछले 7 वर्षों में 71 नए फायर स्टेशन स्थापित किए गये। आज हम प्रदेश में तेजी के साथ तहसील स्तर पर एक-एक फायर स्टेशन स्थापित करने की दिशा में अग्रसर हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही उत्तर प्रदेश पूरे देश में ऐसा राज्य होगा, जहां तहसील स्तर पर फायर स्टेशन होंगे। हमने कानून व्यवस्था में व्यापक रिफॉर्म के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। साथ ही उनके आधुनिकीकरण के लिए समयबद्ध तरीके से कार्यक्रम आगे बढ़ाए गए हैं। उसी का परिणाम है कि प्रदेश में आज अग्निशमन विभाग प्रदेश की इमरजेंसी सेवाओं में एक बेहतरीन सेवा प्रदान करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। हमने विभाग की सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए अब तक लगभग 1400 करोड़ रुपये दिये हैं। ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अपने सरकारी आवास पर आयोजित अग्निशमन सुरक्षा कवच के सुदृढ़ीकरण के लिए 38 अग्निशमन केंद्रों का लोकार्पण/शिलान्यास एवं 35 अग्निशमन वाहनों के फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में कही। इस दौरान सीएम योगी ने विभाग की ओर से लगाई गयी प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया और अधिकारियों से अग्निशमन उपकरणों की जानकारी हासिल की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले सात वर्षों में विभाग के आधुनिकीकरण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। साथ ही समयबद्ध तरीके से विभाग में अधिकारियों की तैनाती की गई है। इसके परिणाम सभी के सामने हैं। पहले अक्सर उद्यमी एनओसी को लेकर शिकायतें करते थे।हमने उसमें कई बदलाव कर उसे सरल किया। यही वजह है कि पिछले कुछ वर्षों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग में काफी सुधार हुआ है। सीएम योगी ने कहा कि फायर टेंडर के रिस्पांस टाइम को कम से कम करने पर जोर होना चाहिये ताकि जन-धन की हानि को कम से कम किया जा सके। पिछले कुछ वर्षों में इसमें काफी सुधार भी हुआ है। यही वजह है कि 33,000 से अधिक अग्नि दुर्घटनाओं में 3,780 जनहानि को रोका गया। साथ ही 5000 से अधिक पशुओं के साथ ही 150 करोड़ रुपये की संपत्ति को नष्ट होने से बचाया गया। इसके अलावा विभाग तेज लू के दौरान फसलों में आग लगने की घटनाओं पर काबू पाने के लिए सदैव खड़ा रहता है। इसे ही ध्यान में रखते हुए हमने आपात सेवाओं का उच्चीकरण करने का कार्य किया है। इस दिशा में न केवल अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकरण बल्कि प्रदेश में एसडीआरएफ के गठन की कार्रवाई को भी पूरा किया गया है। आज एसडीआरएफ की छह कंपनियां काम कर रही हैं। साथ ही साथ प्रदेश के अंदर स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन करते हुए महत्वपूर्ण इमारतों और संस्थाओं की सुरक्षा के दायित्व को पूरा किया है। इन प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए प्रदेशवासियों, निवेशकों और टूरिस्ट के विश्वास को और मजबूत करना है। इसी के तहत पहले चरण में जनपद स्तर और दूसरे चरण में तहसील स्तर पर एक से डेढ़ वर्ष में फायर स्टेशन स्थापित हो जाएंगे।

लोगों को करें प्रशिक्षित मदद के लिए करें प्रेरित

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विभाग रिस्पांस टाइम को कम करता है तो कॉमन मैन के मन में विभाग और शासन के प्रति विश्वास मजबूत होगा। उसके लिए सहायता को पहुंचाना हमारा दायित्व है। हमें स्कूल और कॉलेज में बच्चों के प्रशिक्षण के लिए भी प्रयास करना चाहिए, उनकी काउंसिलिंग को भी कार्यक्रम का हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि सामान्य दिनों में केवल विभाग के भरोसे ही रहकर नहीं बल्कि घटना घटित होते ही बचाव शुरू हो यह महत्वपूर्ण है। बचाव के लिए हम लोगों को पहले से ही तैयार करें। अग्निकांड के लिए कौन-कौन सी लापरवाही जिम्मेदार होती हैं, कैसे हम जनधन की हानि को रोक सकें,

इसके प्रति लोगों को पहले से तैयार कर सकें तो घटना के बाद जब तक सहायता पहुंचती है तब तक लोग स्वयं भी अपने स्तर पर बचाव अभियान की शुरूआत कर सकते हैं। हर घटना हमारे लिए एक सबक होनी चाहिए और फिर उस सबक को लोगों तक पहुंचाना चाहिए, ताकि लापरवाही से बचा जा सके। सीएम ने कहा कि कहीं कोई दुर्घटना होती है तो अक्सर लोग वहां पर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी करते रहते हैं। उस समय हमें सबसे पहले वहां पर लोगों को बचाना चाहिए, राहत कार्यों में भाग लेना चाहिए। हमें इन सभी चीजों से अपने आप को तैयार करना होगा। कार्यक्रम में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, जलशक्ति मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह, मुख्य सचिव दुगार्शंकर मिश्र, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, डीजीपी प्रशांत कुमार, महानिदेशक अग्निशमन एवं आपात सेवा अविनाश चंद्र आदि शामिल हुए।

शेख शाहजहां पार्टी से 6 साल के लिए सस्पेंड

मामले की जांच अब सीआईडी से करवाएंगी ममता दीदी, पुलिस की गिरफ्त में भी पूरे ठसक में आया नजर

एजेंसी

नई दिल्ली। ईडी अधिकारियों पर हमले के आरोपी 55 दिनों बाद पुलिस की गिरफ्त में आए शाहजहां शेख को 10 दिनों की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। इससे पहले कोर्ट ने भी शाहजहां शेख की जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग पर वकील को फटकार लगाई है। अब संदेशखाली के आरोपी शेख शाहजहां को गिरफ्तारी के बाद तृणमूल कांग्रेस ने 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही ममता सरकार अब पूरे मामले की जांच सीआईडी से करवाने का ऐलान किया है। शाहजहां शेख के खिलाफ दर्ज मामलों की जांच का जिम्मा संभाल लिया। टीएमसी नेता

शाहजहां शेख को उत्तर 24 परगना जिले के मिनाखान से गिरफ्तार किया गया था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। तृणमूल के ताकतवर नेता शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने और 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजे जाने के कुछ घंटों बाद, भाजपा ने पश्चिम बंगाल पुलिस की शारीरिक भाषा के साथ उनकी शारीरिक भाषा पर सवाल उठाया और कहा कि यह स्पष्ट है कि शाहजहां को ममता बनर्जी की पुलिस द्वारा संरक्षित किया जा रहा था। और अब फिर से पुलिस हिरासत उसे पश्चिम बंगाल पुलिस की 'मेहमान-नवाजी' में भेज देती है।

⇨ शाहजहां शेख के खिलाफ दर्ज मामलों की जांच का जिम्मा संभाल लिया। टीएमसी नेता शाहजहां शेख को उत्तर 24 परगना जिले के मिनाखान से गिरफ्तार किया गया था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी।

विरासत और विकास को एक साथ लेकर चल रही हमारी सरकार: मोदी

मोदी ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में भारत के कई राज्यों ने विकसित बनने का संकल्प लिया है क्योंकि विकसित राज्यों से ही विकसित भारत बनेगा। आज मध्य प्रदेश इस संकल्प में हमारे साथ जुड़ रहा है। मैं आप सभी को बधाई देता हूँ!

एजेंसी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में लगभग 17,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार विरासत और विकास को कैसे एक साथ लेकर चलती है, इसका उदाहरण उज्जैन में लगी वैदिक घड़ी भी है। बाबा महाकाल की नगरी कभी पूरी दुनिया के लिए काल गणना का केंद्र थी, लेकिन उस महत्व को भुला दिया गया था। अब हमने विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी फिर से स्थापित की है। उन्होंने कहा कि टढ की सभी लोकसभा सीटों को एक साथ लगभग 17 हजार करोड़ रुपये की विकास परियोजनाएं मिली हैं। ये परियोजनाएं टढ के लोगों का जीवन आसान बनाएंगी, यहां निवेश और नौकरियों के नए अवसर बनाएंगी। इन परियोजनाओं के लिए सभी को बहुत बहुत बधाई। मोदी ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में भारत के कई राज्यों ने विकसित बनने का संकल्प लिया है क्योंकि विकसित राज्यों से ही विकसित भारत बनेगा। आज मध्य प्रदेश इस संकल्प में हमारे साथ जुड़ रहा है। मैं आप सभी को बधाई देता हूँ! उन्होंने कहा कि आज चारों तरफ एक ही बात सुनाई देती है- अबकी बार 400 पार! पहली बार ऐसा हुआ है जब जनता ने खुद अपनी प्रिय सरकार की वापसी के लिए ऐसा नारा बुलंद कर दिया है। ये नारा भाजपा ने नहीं, बल्कि देश की जनता-जनार्दन का दिया हुआ है। मोदी की गारंटी पर देश का इतना विश्वास भाव-विभोर करने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार और कांग्रेस सरकार के बीच का क्या अंतर होता है, इसका उदाहरण सिंचाई योजना भी है। 2014 से पहले के 10 वर्षों में देश के करीब 40 लाख हेक्टेयर भूमि को सूक्ष्म सिंचाई के दायरे में लाया गया था, लेकिन बीते 10 वर्षों में इसका दोगुना करीब 90 लाख हेक्टेयर खेती को सूक्ष्म खेती से जोड़ा गया है। ये दिखाता है, भाजपा सरकार यानी गति भी, प्रगति भी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गांव को आत्मनिर्भर बनाने पर बहुत बल दे रही है। इसके लिए सहकारिता का विस्तार किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं टढ के हर नौजवान को, विशेष रूप से फर्स्ट टाइम वोटर को कहूंगा कि आपके लिए बीजेपी सरकार नए अवसर बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रख रही। आपके सपने ही मोदी का संकल्प है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने तो मैन्युफेक्चरिंग की हमारी पारंपरिक ताकत को भी बर्बाद कर दिया था। कुछ साल पहले तक हमारे बाजार और हमारे घर विदेशी खिलौनों से भरे थे।

हिमाचल संकट पर कांग्रेस का मोदी-शाह पर तंज

तथाकथित चाणक्य पूरी तरह से फेल हो गए: जयराम रमेश

एजेंसी

नई दिल्ली। हिमाचल प्रदेश में जारी राजनीतिक संकट के बीच कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के शीर्ष नेता राज्य में निर्वाचित कांग्रेस सरकार को गिराने और अस्थिर करने में विफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुरानी पार्टी के नेताओं के हस्तक्षेप और कांग्रेस के पर्यवेक्षकों की तत्परता के कारण पहाड़ी राज्य में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। राज्यसभा चुनाव के बाद हिमाचल प्रदेश में उत्पन्न हुई सियासी संकट पर फिलहाल कुछ महीनो का ब्रेक लगता दिखाई दे रहा है। जयराम रमेश ने कहा कि हिमाचल को लेकर मीडिया में तरह-तरह की बातें चल रही हैं। लेकिन हम एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना

चाहते हैं। हिमाचल में प्रधानमंत्री और तथाकथित चाणक्य पूरी तरह से फेल हुए हैं। कांग्रेस नेतृत्व के हस्तक्षेप और हमारे पर्यवेक्षकों की तत्परता के बाद वहां स्थिति पूरी तरह से कांग्रेस के नियंत्रण में है। उन्होंने आगे कहा कि दूसरे राज्यों की तरह बीजेपी ने हिमाचल में भी जनता द्वारा चुनी हुई।

निचली अदालतों, उच्च न्यायालयों के स्थगन आदेश अपने आप रद्द नहीं हो सकते: उच्चतम न्यायालय

एजेंसी

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को व्यवस्था दी कि दीवानी और आपराधिक मामलों में निचली अदालत या उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये स्थगन आदेश छह माह के बाद आपने आप रद्द नहीं हो सकते। प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-सदस्यीय संविधान पीठ 2018 के अपने उस फैसले से सहमत नहीं हुई, जिसमें कहा गया था कि निचली अदालतों के स्थगन आदेश अपने आप रद्द हो जाने चाहिए, जब तक कि उसे विशेष रूप से बढ़ाया न जाए। फैसले में (इस विषय पर) दिशानिर्देश जारी करते हुए यह भी कहा गया है कि

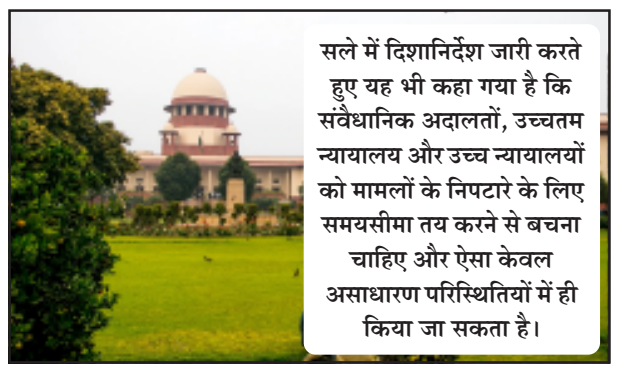

सले में दिशानिर्देश जारी करते हुए यह भी कहा गया है कि संवैधानिक अदालतों, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को मामलों के निपटारे के लिए समयसीमा तय करने से बचना चाहिए और ऐसा केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किया जा सकता है।

संवैधानिक अदालतों, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को मामलों के निपटारे के लिए समयसीमा तय करने से बचना चाहिए और ऐसा केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किया जा सकता है। पीठ ने दो अलग-अलग, लेकिन सहमति वाले फैसले सुनाये। न्यायमूर्ति ए. एस. ओका ने कहा, संवैधानिक अदालतों को मामलों का फैसला करने के लिए कोई समयसीमा तय नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जमीनी स्तर के मुद्दे केवल संबंधित अदालतों को ही पता होते हैं और ऐसे आदेश केवल असाधारण परिस्थितियों में ही पारित किए जा सकते हैं।

मैं विदा होने के लिए तैयार: कमलनाथ

एजेंसी

नयी दिल्ली। अपने भाजपा में जाने की चर्चा को खारिज करने

के एक दिन बाद, कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ ने बुधवार को पार्टी कार्यकताओं से कहा कि वह खुद को उन पर "थोपेंगे" नहीं और अगर वे उन्हें चाहेंगे तो "छोड़" देंगे। मध्य प्रदेश में अपने गृह क्षेत्र छिंदवाड़ा के हर्रई में पार्टी कार्यकताओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए 77 वर्षीय नेता ने कहा कि उन्हें कई वर्षों से उनका प्यार और विश्वास मिल रहा है। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने सभा में कहा, "अगर आप कमलनाथ को विदाई देना चाहते हैं।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के तीन pcs को किया गया रिलीव

कंचन उजाला

लखनऊ। Osd प्रिया सिंह , osd श्रद्धा चौधरी, osd रविनंद त्रिपाठी का हुआ था तबादला अधिकारी तबादले के बावजूद जमे थे एलडीए में शासन स्तर तक चक्कर लगाने के बाद भी नही मिली राहत Osd प्रिया सिंह, osd श्रद्धा चौधरी के ऊपर अवैध निर्माण को लेकर उठे थे सवाल।

इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो पुराने भवन में जाएंगे: संजय राउत

एजेंसी

नई दिल्ली। शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने गुरुवार को वर्तमान संसदीय व्यवस्था की तीखी आलोचना की और नए संसद भवन की तुलना "पांच सितारा जेल" से की, जहां उत्पादकता गंभीर रूप से बाधित है। राउत ने सांसदों के सामने आने वाली समस्याओं पर निराशा व्यक्त करते हुए मीडिया कर्मियों से कहा, "किसी को नई दिल्ली में सेंट्रल विस्टा की स्थिति देखनी चाहिए।" उन्होंने कहा कि नई संसद पांच सितारा जेल की तरह है जहां आप काम नहीं कर सकते।

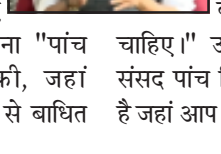

शेख शाहजहां को पुलिस का संरक्षण

भाजपा का सवाल, उसे ईडी को क्यों नहीं सौंप रही ममता सरकार?

एजेंसी

नई दिल्ली। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता शेख शाहजहां को कड़ी फटकार लगाई, जिन्हें पिछले महीने उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखली में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम पर हुए हमले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।

उच्च न्यायालय ने कहा कि गिरफ्तार टीएमसी नेता "किसी भी सहानुभूति के पात्र नहीं हैं"। कोर्ट ने शाहजहां शेख को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। मिनाखान से तड़के गिरफ्तारी के बाद शेख को सुबह 10 बजकर 40 मिनट पर बशीरहाट की अदालत में पेश किया गया। राज्य पुलिस ने शेख को 14 दिन की हिरासत में भेजे जाने का अनुरोध किया था लेकिन अदालत ने 10 दिन की पुलिस हिरासत की मंजूर दी।

भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि एजेंसियों की 56 दिनों की तलाश के बाद आखिरकार शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया गया है। चिंता की बात यह है कि उनके गिरफ्तारी वारंट में महिलाओं के खिलाफ अपराध का कोई जिक्र नहीं किया गया है।

भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद् की तीन दिवसीय कार्यशाला / प्रदर्शनी

" उत्तर प्रदेश एग्रोटेक-2024" का शुभारंभ करेंगे उद्यान मंत्री श्री दिनेश प्रताप सिंह

कार्यशाला एवं प्रदर्शनी 1 मार्च से 3 मार्च तक भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान में संपन्न होगी

संवाददाता

लखनऊ। भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद अपनी सालाना कार्यशाला व प्रदर्शनी "एग्रोटेक 2024-डेवलपमेंट मीट ऑन उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर" का आयोजन कल एक मार्च से करने जा रहा है। प्रदर्शनी और कार्यशाला आयोजन भारतीय कृषि खाद्य परिषद उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के सहयोग से आयोजित कर रहा है। कार्यक्रम के प्रायोजक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और सह प्रायोजक आईपीएल बायोलोजिकल्स लिमिटेड है। उक्त प्रदर्शनी व कार्यशाला का शुभारंभ प्रदेश के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री दिनेश प्रताप सिंह जी करेंगे। प्रदर्शनी शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान राज्य सभा के सांसद श्री अशोक बाजपेयी जी, वरिष्ठ आईएएस व

एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कृषि विभाग डॉ देवेश चतुवेर्दी, नाबार्ड के सीजीएम श्री एस के डोरा, डॉ अनीस कुमार शर्मा डायरेक्टर टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भी प्रमुख रूप से मौजूद रहेंगे। तीन दिवसीय कार्यक्रम के प्रथम चरण में प्रदर्शनी का शुभारंभ होने के साथ साथ विभिन्न सत्र का आयोजन भी होगा। जिसमे प्रदेश के आला अधिकारी सहित कृषि विशेषज्ञ शामिल रहेंगे और प्रतिभागियों से विषय सम्बंधित संवाद कर उनको कृषि नवाचार से अवगत कराएँगे। विभिन्न सत्रों में प्रमुख रूप से कृषि सम्बंधित विषयो पर सारगर्भित चर्चा और संवाद का आयोजन प्रस्तावित है। कार्यक्रम के अंत में प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदी बेन द्वारा "यूपी इनोवेटिव अवार्ड्स 2024 का वितरण तमाम कृषको को किया जायेगा। साथ ही साथ प्रदर्शनी के बेस्ट स्टाल अवार्ड भी वितरित किया जायेगा।

कार्यक्रम की रूपरेखा :

कार्यक्रम स्थलः भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, तेलीबाग

कार्यक्रम तिथिः 1 मार्च से 3 मार्च 2024

समय : प्रातः 10: 30 से सांय 5: 30 तक

सम्पादकीय

क्या लोकसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन भाजपा के लिये चुनौती बन पायेगा?

अंधेरों एवं निराशा के गर्त में जा चुके एवं लगभग बिखर चुके इंडिया गठबंधन के लिए कुछ अच्छी खबरों ने जहां उसमें नये उत्साह का संचार किया है वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिये चिन्ता के कारण उत्पन्न किये हैं। पहले उत्तर प्रदेश और फिर दिल्ली में समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी से सीट बंटवारे पर बनी सहमति ने टूट की कगार पर पहुंचे इंडिया गठबंधन में वर्ष 2024 के आम चुनावों को लेकर संभावनाभरी तस्वीर को प्रस्तुत किया है। अब ये चुनाव दिलचस्प होने के साथ कुछ सीटों पर कांटे की टक्कर वाले होंगे। इन नये बन रहे चुनावी समीकरणों के बावजूद भाजपा के लिये अभी कोई बड़ा संकट नहीं दिख रहा है। भले ही इंडिया गठबंधन डींगे हांके कि वह भाजपा एवं उसके गठबंधन के लिए कड़ी चुनौती पेश करने की स्थिति आ गयी है। भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों का जब गठबंधन बना तभी यह आशंका की गयी कि यह कितनी दूर चल पायेगा, टिक पायेगा भी या नहीं? कुछ हालात तो ऐसे भी बने कि इसके तार-तार होने की संभावनाएं बलवती हुईं। भले ही अब कुछ सीटों पर दलों के बीच सहमति बनी हो लेकिन अभी कई महीने निकल जाने के बाद भी विधिवत रूप से इंडिया गठबंधन के संयोजक का नाम घोषित नहीं हो पाना अनेक सन्देहों एवं अटकलों का कारण बना हुआ है। सत्ता तक पहुंचने के लिए जिस प्रकार दल-टूटन व गठबंधन हो रहे हैं इससे सबके मन में अकल्पनीय सम्भावनाओं की सिहरन उठती है। राष्ट्र और राष्ट्रीयता के अस्तित्व पर ही प्रश्नचिन्ह लगने लगा है। कुछ अनहोनी होगी, ऐसा सब महसूस कर रहे हैं। प्रजातंत्र में टकराव होता है। विचार फर्क भी होता है। मन-मुटाव भी होता है पर मयार्दापूर्वक। लेकिन अब इस आधार को ताक पर रख दिया गया है। राजनीति में दुश्मन स्थाई नहीं होते। अवसरवादिता दुश्मन को दोस्त और दोस्त को दुश्मन बना देती है। यह भी बड़े रूप में देखने को मिल रहा है। राजनीति नफा-नुकसान का खेल बन रहा है, मूल्य बिखर रहे हैं। चारों ओर सत्ता की भूख बिखरी है। पिछले कुछ समय से इंडिया गठबंधन को एक के बाद एक कई झटके लगे। पहले तो कांग्रेस ने ही पिछले साल दिसंबर के विधानसभा चुनावों में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद में गठबंधन से जुड़ी बातचीत को ठंडे बस्ते में डाले रखा। बातचीत शुरू भी हुई तो नेताओं में न तो पहले जैसा जोश दिखा और न वैसी राजनीतिक जिजीविषा महसूस हुई। फिर गठबंधन के प्रस्ताव पर सबसे बढ़-चढ़कर काम करने वाले नीतीश कुमार ही उसे छोड़ गए। यूपी में रालोद के जयंत चौधरी भी इंडिया गठबंधन का हाथ थामते-थामते एनडीए में शामिल हो गए। इंडिया गठबंधन एवं कांग्रेस ने अनेक झटके झेले। छोटे-बड़े नेताओं के कांग्रेस छोड़ने का सिलसिला भी तेज हुआ। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण का नाम खास तौर पर चर्चित रहा। इसे चाहे इन नेताओं का व्यक्तिगत अवसरवाद कहें या भाजपा और एनडीए नेतृत्व की सक्रियता एवं राजनीतिक कौशल इतना तय है कि इन नेताओं को कांग्रेस का भविष्य खास अच्छा नहीं दिख रहा। आम आदमी पार्टी एवं समाजवादी पार्टी जैसे दल अपनी साख बचाने एवं सत्ता के करीब बने रहने के लिये सीटों के बंटवारे पर सहमत हुए हैं, उसमें कांग्रेस का घुटने टेकना भी उसकी टूटती सांसों को बचाने की जद्दोजहद ही कहीं जायेगी। कांग्रेस एवं अन्य दलों के बीच सहमति के स्वर उभरने से आगामी लोकसभा चुनाव में अच्छा मुकाबला दिख सकता है। लेकिन अहम सवाल तो यही है कि क्या गठबंधन की गाड़ी आगे और हिचकोले नहीं खाएगी? क्या यह दावा पूरी दृढ़ता से किया जा सकता है? अरविन्द ने कांग्रेस से सीटों पर सहमति बनाकर पलटूराम ही बने हैं। जी-भरकर एक-दूसरे को कोसने वाले जब हाथ मिलाएं तो आश्चर्य होना स्वाभाविक है। देखा जाये तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच चुनावी गठबंधन होना मूल्यहीनता एवं सिद्धान्तहीनता की चरम पराकाष्ठा है क्योंकि कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ लड़ कर और आंदोलन खड़ा करके ही आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब की सत्ता से कांग्रेस को बाहर किया और अपनी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई। आम आदमी पार्टी के चमत्कारिक प्रदर्शन के चलते ही गुजरात में कांग्रेस ने अब तक का सबसे निराशाजनक प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी ने गोवा में भी कांग्रेस को काफी नुकसान पहुँचाया और हरियाणा में भी अपने संगठन का आधार बढ़ाया। ताजा कांग्रेस एवं आम आदमी पार्टी की सहमति से कांग्रेस को ही नुकसान होना है। केजरीवाल की बजाय ममता बनर्जी ने अलग छाप छोड़ी है। उसने बंगाल में कांग्रेस के लिए उनकी मौजूदा दो लोकसभा सीटों को ही छोड़ने की बात कह कर कांग्रेस के अधिक सीटों पर दावा करने के कारण स्वतंत्र चुनाव लड़ने की घोषणा कर गठबंधन को धराशायी किया। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल ही नहीं, बल्कि त्रिपुरा, असम और गोवा में भी स्वतंत्र चुनाव लड़ने की बात कह रही हैं, जिससे कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में निराशा ही हाथ लगेगी। इंडिया गठबंधन के नये बन रहे सकारात्मक परिदृश्यों के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक सेहत पर कोई असर न झलकना उनकी राजनीतिक परिपक्वता की परिचायक है। 2024 के चुनावों में भाजपा के लिए 370 और एनडीए के लिए 400 सीटों का लक्ष्य तय करने के मोदी के लक्ष्य के सामने अभी भी कोई बड़ी चुनौती दिख नहीं रही है।

लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु में हो सकता है त्रिकोणीय मुकाबला

के आर सुधामन

2024 के लोकसभा चुनावों के लिए तमिलनाडु में राजनीतिक सीटों की साझेदारी के संबंध में अभी तक विभिन्न पार्टियों के बीच समझौते पूरे नहीं हुए हैं। राज्य में आधी सदी या उससे भी अधिक समय से राजनीति दो द्रविड़ पार्टियों द्रमुक और अन्नाद्रमुक के इर्द-गिर्द घूमती रही है। कुछ साल पहले द्रमुक के संरक्षक एम करुणानिधि और अन्नाद्रमुक सुप्रीमो जे जयललिता की मृत्यु के बाद से दोनों दलों, जिनके पास लगभग 30 से 35 प्रतिशत वोट शेयर थे, निश्चित रूप से कम हो गये हैं। तब से दोनों द्रविड़ पार्टियों का व्यक्तिगत वोट शेयर घटकर 20-25 प्रतिशत रह गया है और जैसा कि हमने पिछले कुछ चुनावों में देखा था, जो भी पार्टी बेहतर गठबंधन बनाती है, वह जीतती है, चाहे वह तमिलनाडु विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का। तमिलनाडु में सत्ता में आने वाले पार्टी संयोजन को लगभग 40 प्रतिशत वोट हासिल करने होते हैं, इसलिए चुनाव जीतने के लिए आवश्यक अतिरिक्त 15 से 20 प्रतिशत वोट गठबंधन सहयोगियों से आना होता है, जिसमें से कोई भी पार्टी शामिल हो जाती है। राष्ट्रीय पार्टियों ने अतीत में किसी न किसी द्रविड़ पार्टियों के साथ गठबंधन किया है, जिससे उनके प्रति कोई वैचारिक बाधा नहीं होने का संकेत मिलता है। हर चुनाव में एक तीसरा मोर्चा भी होता है, जिसे लगभग 15-20 प्रतिशत वोट मिलते हैं क्योंकि तमिलनाडु की आबादी का एक प्रतिशत ऐसा है, जो द्रविड़ पार्टियों या उनके संयोजन में से किसी को वोट नहीं देता है। पिछले कुछ समय से तमिलनाडु के चुनावों का यही गणित रहा है। हालांकि कांग्रेस के 1967 में राज्य की सत्ता से बाहर होने पर भी हर निर्वाचन क्षेत्र में उसके कुछ प्रतिबद्ध मतदाता हैं और वे लगभग 8-12 प्रतिशत वोट बनाते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि हवा किस तरफ है। इसलिए कांग्रेस जिस द्रविड़ पार्टी के साथ गठबंधन करती है, उसे वर्तमान परिस्थितियों में चुनाव जीतने में बढ़त हासिल होती है। हाल ही में, अन्नामलाई के नेतृत्व में, भाजपा तमिलनाडु में एक बड़ी ताकत बनकर उभर रही है, खासकर युवाओं के बीच, जो दो द्रविड़ पार्टियों के बढ़ते भ्रष्टाचार और जाति-आधारित राजनीति से तंग आ चुके हैं। पिछले 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा का वोट शेयर करीब 4-5 फीसदी था, इस बार 14-15 फीसदी तक जाने की उम्मीद है। भाजपा, जिसने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी भी द्रविड़ पार्टी के साथ गठबंधन का हिस्सा नहीं होगी, दिवंगत फिल्मस्टार से राजनेता बने विजयकांत की पार्टी जैसी कुछ छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन कर सकती है और इससे अतिरिक्त 10-12 सीटें मिल सकती हैं। फिलहाल डीएमके इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन कांग्रेस के साथ सीटों की साझेदारी पर चर्चा अभी शुरू नहीं हुई है। अगर राज्य में बड़ा साझेदार होने के नाते डीएमके सीट बंटवारे की कवायद में सख्त रुख अपनाती है, तो कांग्रेस के सख्त रुख अपनाने की संभावना हमेशा बनी रहती है। एआईएडीएमके ने कुछ समय पहले भाजपा के साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया है और बार-बार यह स्पष्ट किया है कि वह कम से कम 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा से हाथ नहीं मिलायेगी। अन्नाद्रमुक को भाजपा का कनीय साझेदार होने मंजूर नहीं है क्योंकि उसे डर है कि अंततरू पार्टी भाजपा द्वारा हाशिए पर धकेल दी जायेगी जैसा कि महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्यों में शिवसेना और जद (यू) के साथ हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम और शशिकला के भतीजे टीटीवीदिनाकरन के नेतृत्व वाले अन्नाद्रमुक के अलग-अलग समूहों के भाजपा के साथ जाने की संभावना के संकेत हैं। तमिलनाडु में गठबंधन को लेकर अभी साफ तस्वीर सामने आना बाकी है। परंपरागत रूप से द्रमुक के साथ रहने वाली कुछ छोटी पार्टियों ने द्रविड़ पार्टी के साथ जाने का अपना फैसला दोहराया है। अब तक डीएमके ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 1 लोकसभा सीट दी है। दूसरी सीट कोंगुनाडुमक्कलदेसियाकाची को दिए गए। ये डीएमके के दो छोटे साझेदार हैं, जिन्होंने पिछली बार भी गठबंधन का हिस्सा बनकर चुनाव लड़ा था। इस हफ्ते कांग्रेस से बातचीत होने की उम्मीद है।आई यूएमएल रामनाथपुरम संसदीय सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेगी। तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीटें हैं तथापुडुचेरी से एक। अभिनेता से नेता बने कमल हासन, जो मक्कलनीदिमय्यम (एमएनएम) के प्रमुख हैं, ने संकेत दिया है कि वह गठबंधन के लिए बातचीत कर रहे हैं। वह खुद इस बार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं और संकेत हैं कि वह डीएमके गठबंधन के साथ जायेंगे। जाहिर तौर पर वह निर्णय लेने से पहले द्रमुक-कांग्रेस सीट साझाकरण

वार्ता के नतीजे का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल डीएमकेकांग्रेस, विदुथलाईचिरूथैगलकाची (वीसीके), मारुमलारची द्रविड़ मुनेत्रकड़गम (एमडीएमके), वाम दल समेत अन्य पार्टियों को एकजुट रख रही है और उनके साथ सीट-बंटवारे की बातचीत शुरू कर रही है। राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी, अन्नाद्रमुक, जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) से बाहर हो गई है, द्रमुक के विकल्प के रूप में पेश करने के लिए एडप्पादी के पलानीस्वामी के तहत अधिक से अधिक पार्टियों को लाने का प्रयास कर रही है। हाल ही में, एडप्पादी ने सोशलडेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) की बैठक में भाग लिया और भाजपा की आलोचना करते हुए कहा कि वे अल्पसंख्यकों के लिए खड़े हैं। उन्होंने दोहराया था कि वे लोकसभा चुनाव या 2026 में होने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में भाजपा से हाथ नहीं मिलायेंगे। अन्नाद्रमुक के प्रमुख नेताओं में से एक सी वीशनमुगम ने पट्टालीमक्कलकाची के संस्थापक डॉ. एस रामदास के साथ बातचीत की और इस बैठक को महत्व दिया जा रहा है क्योंकि राज्य की प्रमुख पार्टियों में से एक पीएमके ने अभी तक गठबंधन पर अपने फैसले की घोषणा नहीं की है। पिछले हफ्ते, विशेष कार्यकारी बैठक के दौरान, पीएमके ने राज्य और देश दोनों के कल्याण की परवाह करने वाली पार्टियों के साथ गठबंधन में आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने के अपने फैसले सहित कई प्रस्ताव पारित किये थे। एआईएडीएमके के ये कदम उठाने के साथ ही भाजपा भी गैर-द्रविड़ नेताओं से बातचीत कर रही है। जबकि अन्नाद्रमुकपीएमके और प्रेमलताविजयकांत के नेतृत्व वाली देसियामुरपोक्कू द्रविड़ कड़गम (डीएमडीके) के साथ भी बातचीत कर रही है, सूत्रों ने कहा कि बाद वाले के भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल होने की संभावना है। डीएमडीके की कार्यकारी और सामान्य परिषद की बैठक के दौरान, प्रेमलता ने कहा था कि वे किसी भी पार्टी के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इससे पहले, उन्हें लिखित रूप में राज्यसभा सीट का वायदा करना होगा। डीएमडीके के अलावा, टीटीवीदिनाकरन की अम्मा मक्कलमुनेत्रकड़गम, टीआरपारीवेंधर की इंडिया जनानायगाकाची (आईजेके), और के कृष्णास्वामी की पुथियातमिड़गम जैसी अन्य पार्टियां हैं जिनके एनडीए का हिस्सा बनने की संभावना है। पूर्व मुख्यमंत्री और अन्नाद्रमुक से निष्कासित नेता ओ पन्नीरसेल्वम संभवतरू भगवा पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। जी के मूपनार के बेटे जी के वासन की अगुवाई वाली तमिल मनीला कांग्रेस भी भाजपा के साथ जा सकती है। वह एआईएडीएमके के साथ भी जा सकते हैं। फिलहाल गठबंधन को लेकर तस्वीर अभी भी साफ नहीं है और सभी संभावनाएं अभी भी खुली हैं। उन्हें आकार लेने में कुछ सप्ताह या उससे भी अधिक समय लग सकता है। लेकिन एक बात तो साफ है कि लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु में त्रिकोणीय मुकाबला होगा। एक का नेतृत्व द्रमुक, दूसरे का नेतृत्व अन्नाद्रमुक और तीसरे का नेतृत्व भाजपा करेगी। अगर डीएमके कांग्रेस के साथ जाती है, तो कई छोटी पार्टियां भी उसके साथ चली जायेंगी, जिससे यह एक मजबूत गठबंधन बन जायेगा। उस स्थिति में, अन्नाद्रमुक को मुख्य नुकसान होने की संभावना है। लेकिन तमिलनाडु में द्रमुक शासन के खिलाफ नाराजगी भी बढ़ रही है और यह मुख्य रूप से 2026 के राज्य विधानसभा चुनावों में दिखाई देगी।

देश जो सब का था, अब कुछ का होकर रह गया है

डॉ. दीपक पाचपोर

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा जनवरी की 22 तारीख को तमाम वीआईपियों की मौजूदगी में अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राणप्रतिष्ठा के जरिये देश में रामराज्य की स्थापना किये अभी एक महीना ही हुआ है और उधर कर्नाटक के राजाजीनगर मेट्रो स्टेशन पर जो कुछ हुआ उसने बता दिया है कि देश अब किसका है। इस स्टेशन पर एक किसान को इसलिये मेट्रो ट्रेन में चढ़ने नहीं दिया गया क्योंकि उसने गंदे कपड़े पहन रखे थे और सिर पर एक गठरी थी। यह घटना बताती है कि जो देश कभी हर किसी का हुआ करता था अब थोड़े से लोगों का होकर रह गया है। कहने को तो बेंगलुरु मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड ने यह कहकर उक्त पर्यवेक्षक को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है कि श्मेट्रो एक समावेशी सार्वजनिक परिवहन है श् हालांकि निगम ने उक्त यात्री से माफी मांग ली है पर यह घटना बतलाती है कि कई तरह की गैरबराबरियों वाले इस देश में किसी की माली हालत देखकर भेदभाव करने की प्रवृत्ति भी बढ़ चली है। समाज की यह बदलती मानसिकता इसलिये घातक है क्योंकि इससे एक और प्रकार के सामाजिक विभाजन की जमीन तैयार होती दिखती है। अगर एक मोटा अंदाजा लगाएं तो यह पर्यवेक्षक सम्भवतरू उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जिसे जाहिर है कि मोटी तनख्वाह मिलती होगी। यह उस खाये-पिये-अघाये वर्ग का बंदा है जिसके पास होम लोन के जरिये अपना मकान होना चाहिये, अपने वाहन की किश्तें पटाने के लिये पैसे होंगे ही। पत्नी भी कमाती होगी, बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते होंगे। यह वह वर्ग है जिसके पास बैंक बैलेंस भी होगा, कर्मचारी प्राविडेंट फंड का पैसा जमा हो रहा होगा। सम्भव है कि शेयरों में भी जरूर कुछ निवेश कर रखा होगा। वैसे इसमें कोई बुराई नहीं है। होना भी चाहिये। ये सारे कयास ही हैं परन्तु जो बात साफ है वह यह कि उसने हाल के वर्षों में अपने जैसों या कुछ ऊपर-नीचे वाली स्थिति के लोगों से घृणा करना सीख लिया है। बेशक, यह मानसिकता पिछले 10 वर्षों की देन है। मोदी ने जनसामान्य को भी आडंबर और दिखावे की आदत लगा दी है। भव्यता एवं विलासिता में डूबे लोग अब इस देश को भाने लगे हैं। वे अब सादगी पसंद लोगों को देश के कर्णधार नहीं मानते बल्कि उनकी पसंद के लोग धन्ना सेठ, सिने कलाकार और लकदक ढंग से रहने वाले नेता हैं। यही वह वर्ग है जिसे कोरोना काल में सैकड़ों किलोमीटर धूप में भूखे-प्यासे पैदल चलने वाले मजदूरों व गरीबों की परेशानियां नहीं दिखी थीं बल्कि उन्हें इनकी गंदगी चिंतित करती थी। यह वर्ग मोदी का इसलिये मुरीद है क्योंकि वे किसानों के आंदोलन को कुचलना जानते हैं, श्रम कानूनों को कारखानेदारों और बड़े व्यवसायियों के पक्ष में बदल

रहे हैं। भारत को 5 ट्रिलियन इकानॉमी वाला देश बनने का बेसब्री से इंतजार करने वाला यह वर्ग मानता है कि गरीबों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं को मिलने वाली सब्सिडी को खत्म कर देना चाहिये क्योंकि ये खैरात, मुफ्तखोरी और रेवड़ियां हैं। वे इस तरह की बातें अपने प्रेरणा स्रोत यानी नरेन्द्र मोदी के श्रीमुख से हमेशा सुनते आए हैं। इसी भरोसे पर उन्होंने मोदी को वोट दिया था कि वे ये सारे बेकार के खर्च बन्द कर देंगे। अलबत्ता उन्हें इस बात से कोई उज्र नहीं है कि बड़े फ्रॉडस्टर सरकारी बैंकों का पैसा लेकर भाग जाते हैं। उनके लिये यह भी कोई मसला नहीं है कि लोगों के पास रोजगार नहीं है। पेट्रोल-डीजल, गैस, उपभक्ता वस्तुओं के बढ़ते दाम उन्हें कतई परेशान नहीं करते। वे मानते हैं कि कीमतें बढ़ना समृद्धि की निशानी है। जब बात प्याज, लहसुन की बढ़ती कीमतों पर आ जाती है तो वे यह कहकर दूसरा रास्ता पकड़ लेते हैं-मैं तो प्याज नहीं खाता (ती) जी !श मोदी ने दरअसल यही हिन्दुस्तान बनाया है। 85 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पर निर्भर करते मोदी का रहन-सहन देखें तो रईसजादों से कम नहीं है। वे दिन में तीन-चार बार कपड़े बदलते हैं. करोड़ों की कार और हवाई जहाज में घूमते हैं। महंगे चश्मे और पेन से सुसज्जित मोदी ने कभी कहा था कि वे ऐसा देश बनाएंगे, जिसमें हवाई चप्पल वाले हवाई जहाजों में घूमते हुए दिखेंगे। ऐसा तो हो नहीं पाया, उल्टे अब हवाई चप्पल वालों को मेट्रो में भी चढ़ने नहीं दिया जा रहा है। यह मामला ट्रेन का है, तो उसी की बात कर ली जाये। मोदी ने ट्रेन यात्राओं को इस कदर महंगा कर दिया है कि उससे यात्रा करने के पहले कोई सौ बार सोचता है। मोदी की दिलचस्पी ट्रेन में सुधार करने और लोगों की सहूलियतें बढ़ाने में नहीं वरन महंगी ट्रेनें चलाने में है।

निताशा कौल को लौटाना लोकतंत्र विरोधी आचरण

यूनाइटेड किंगडम की भारतीय मूल की प्रोफेसर निताशा कौल को जबरिया उनके देश लौटाकर एक बार फिर से भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि यहां लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों की बात करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। निताशा कर्नाटक सरकार की ओर से आयोजित एक सम्मेलन में भाग लेने के लिये सम्मानित वक्ता के रूप में आमंत्रित की गई थीं परन्तु उन्हें बेंगलुरु हवाईअड्डे से वापस लंदन भेज दिया गया। वहां के वेस्टमिंस्टर विश्वविद्यालय में अध्यापन करने वाली निताशा 24-25 को कर्नाटक सरकार द्वारा श्संविधान व राष्ट्रीय एकताश सम्मेलन में भाग लेने के लिये आई थीं। वे कश्मीर के मामलों में अपने बेबाक विचारों के लिये जानी जाती हैं। वे नरेंद्र मोदी सरकार की कश्मीर मामले में नीतियों की विरोधी के रूप में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाये जाने का तो विरोध किया ही था, द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर भी सरकार की आलोचना की थी। वैसे तो उन्हें वापस भेजने का कोई स्पष्ट कारण भारत सरकार की ओर से नहीं बतलाया गया है लेकिन स्पष्ट है कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी, भारतीय जनता पार्टी एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विरोधी होने का खामियाजा भुगतना पड़ा है। फिर, यह कार्यक्रम कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की ओर से आयोजित किया गया था, सो मोदी सरकार द्वारा ऐसा करना लाजिमी ही था। अपने एक्स हैंडल पर निताशा ने इस बाबत लिखी पोस्ट में बतलाया है कि उन्हें कर्नाटक सरकार ने आमंत्रित किया था। उनके यात्रा सम्बन्धी सभी दस्तावेज सही थे तो भी उन्हें आव्रजन अधिकारियों की ओर से बेंगलुरु एयरपोर्ट पर हिरासत में रखा गया। उन्हें रोके जाने का किसी ने कोई कारण नहीं बताया। अधिकारी केवल यही कहते रहे कि श्वे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें दिल्ली से ऐसा करने के आदेश मिले हैं।श निताशा का यह भी आरोप है कि उन्हें सोने के लिये तकिया तक नहीं दिया गया और उन्हें अखबारों को ही तकिया बनाकर सोना पड़ा था। खाने-पीने तक नहीं दिया गया। वे यह भी कहती हैं कि उन्हें न आने के लिये केन्द्र सरकार की ओर से कोई आदेश भी नहीं मिला। शुक्रवार को सुबह वे बेंगलुरु हवाईअड्डे पर उतरीं और शनिवार की सुबह वापस लंदन भेज दी गईं। राजनीति शास्त्र एवं अंतरराष्ट्रीय मामलों की प्रोफेसर निताशा का जन्म गोरखपुर में हुआ था। वे एक ऐसे कश्मीरी पंडित के घर में जन्मी थीं जो घाटी छोड़कर आया था। उन्होंने दिल्ली के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से अर्थशास्त्र में स्नातक एवं दिल्ली विवि से उच्च शिक्षा हासिल की है। 1997 में 21 वर्ष की आयु में वे इंग्लैंड चली गयीं। वहां के हल विवि से अर्थशास्त्र व दर्शनशास्त्र में डॉक्टरेट करने के बाद वे वेस्टमिंस्टर विवि में पढ़ाने लगीं। भारत में राष्ट्रवाद, लैंगिक असमानता तथा नागरिक अधिकारों आदि से सम्बन्धित विषयों पर उनके विचार सुर्खियों में आये थे। भाजपा व संघ के विचारों के खिलाफ वे बोलतीं तथा लिखती रहती हैं। वे एक उपन्यासकार तथा कवयित्री के रूप में भी पहचान रखती हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर भाजपा समर्थक उनके खिलाफ कई तरह के आरोप लगा रहे हैं।

मेषः- आपकी महत्वाकांक्षाए सफलता की राह पर संघर्ष हेतु प्रेरित करेंगी। अच्छी भावनाऐं आपके मकसद सफलता दिलाऐंगी। कार्य क्षेत्र में अपनें बौद्धिक क्षमता का लाभ उठाऐंगे।

बृषभः- परिश्रम द्वारा आर्थिक क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे। समय बड़ा मूल्यवान है। अतः इसे व्यर्थ न गंवायें। किसी नए सम्वेदना का प्रभाव नए रिश्ते को जन्म देगा। अभिभावकों का सहयोग प्राप्त होगा।

मिथुनः- परम्पराओ व संस्कारों कें प्रति आस्था बढ़ेगी। निर्थक हीनभाव एवं कुछ साथ के प्रगतिशील व्यक्तियों से ईष्या भाव ठीक नही। अस्थिर मन लक्ष्य के प्रति केन्द्रित होने मे असमर्थ होगा।

कर्कः- किसी महत्वपूर्ण कार्य वश घर से दूर रहना अरुचिकर लगेगा। आपका मिलनसारिता के कारण सम्बन्धो का बिस्तार होगा। कमजोर मनोबल के कारण लक्ष्य के प्रति दृढ़ता का अभाव रहेगा।

सिंहः- किसी महत्वपूर्ण कार्य में थोड़ी कठिनाई का अभास होगा। संवेदनशील मन पूरानी मर्मस्पर्शी घटनाओं से ओत-प्रात होगा। परिवारिक दायित्वों को समयानुकूल पूर्ति हेतु मन चिन्तित होगा।

कन्याः- प्रयासरत क्षेत्रों में अवरोध तथा दाम्पत्य जीवन में कष्ट संभव। परन्तु ईरीय आस्था हर परीस्थिती पर बिजय प्राप्त करेंगे। धैर्यपूर्वक महत्वपूर्ण योजनाओं को क्रियान्वित करें।

तुलाः- घर-परिवार में खुशी का वातावरण रहेगा। पिछले दिनों उत्पन्न को व्यवसायिक अवरोध के हल ढूंढने में मन केद्रित होगा। किसी पुराने मित्र की मध्यस्तता से बिगड़े हुए सम्बन्धो में सुधार होगा।

वृश्चिकः- मनोवांछित सफलता न मिलने से उत्साह में कमी होगी। भौतिक चका-चैंद से प्रभावित मन अभाव की अनुभूति से दुखित होगा। धैर्यहीनता व परिवर्तनशीलता लक्ष्य से दिग्भ्रमित करेगा।

धनुः- परिजनो व मित्रों का सनिध्य से मन प्रसन्न रहेगा। कार्य-पेशे में कोई अवरोधित कार्य सार्थक होने के आसार है। मांगलिक एव सास्कृतिक आयोजनों में सम्मलित होंगे। महत्वपूर्ण कायरे में आलस्य ना करे।

मकरः- कुछ नये सम्बन्द बनेगें। जीवनसाथी से वैचारिक मतभेद सम्भव। कर्तव्य व जिम्मेदारियों से घिरा मन अपनी कल्पनिक आकांक्षाओं से समझौता करने में सक्षम होगा। किसी नई दिशा में रुचि बढ़ेगी।

कुंभः- मन को खराब विचारो से दूर रखते हुए अच्छे कायरे में केन्द्रित करें। नई स्थितियाँ आप मे नई प्रतिभाओं का संचार करेगा। कार्यकुशलता व प्रतिभा का जौहर बिखेरेंगे।

मीनः- अपनी वाणी पर नियंतणरखते हुए सम्बन्धों को मधुर बनाने की चेष्टा करें। प्रतिभा व आत्मबल कुछ महत्वपूर्ण सफलताओ के प्रति आशान्वित करेगा। आर्थिक लाभ के आसार हैं।

अधिकतम मतदान के जरिये ही देश की राजनीति को सुधारा जा सकता है

ललित गर्ग

अधिकतम वोटिंग का वास्तविक उद्देश्य है, जन-जन में लोकतंत्र के प्रति आस्था पैदा करना, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी निश्चित करना, वोट देने के लिए प्रेरित करना। एक जनक्रांति के रूप ह्यभारतीय मतदाता संगठनह्ल इस मुहिम के लिये सक्रिय हुआ है, यह शुभ संकेत है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम से तीन माह के लिए विराम लेते हुए लोकतंत्र के महाकुंभ चुनाव में पहली बार वोटर बने युवाओं से रिकार्ड संख्या में मतदान का आग्रह किया। अधिकतम संख्या में मतदान लोकतंत्र की जीवंतता का प्रमाण होने के साथ लोकतंत्र के बलशाली होने का आधार हैं और जनता की सक्रिय भागीदारी का सूचक है। इस बार लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या लगभग 97 करोड़ है, इनमें बड़ी संख्या युवाओं की है। इसीलिये मोदी ने मतदान में युवाओं की सक्रिय भागीदारी का आह्वान करके एक जागरूक, सक्षम एवं जुझारु राजनेता का परिचय दिया है। अधिकतम मतदान भारतीय लोकतंत्र को अधिक स्वस्थ, सुदृढ़ एवं पारदर्शी बनाने की एक सार्थक मुहिम है। सभी मतदाताओं को मतदान के प्रति वैसा ही उत्साह दिखाना चाहिए जैसा कुछ समय से महिलाएं दिखा रही हैं। प्रधानमंत्री ने युवाओं से यह भी अपील की कि वे राजनीतिक गतिविधियों का हिस्सा बनें और राजनीतिक-चचाओं को लेकर जागरूक भी रहें। विशेषतः विभिन्न राजनीतिक दलों की लोकलुभावन घोषणाओं एवं चुनावी घोषणा पत्रों पर युवाओं को गहराई से जानकारी हासिल करना चाहिए कि इन घोषणाओं का आधार क्या है, इनके लिये धन कहां से आयेगा? चुनावी तैयारियों का जायजा लेने चेन्नई गए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने इसी बात को उठाते हुए कहा है कि यदि राजनीतिक दलों को अपने घोषणापत्रों में लोकलुभावन वादे करने का अधिकार है तो मतदाताओं को यह जानने का हक भी है कि क्या वे वादे व्यावहारिक हैं और उन्हें लागू करने के लिए धन का प्रबंध कहां से किया जाएगा। अगले माह लोकसभा चुनाव की संभावित घोषणा और उसके चलते आचार संहिता लागू हो जायेगी। अधिकतम मतदान लोकतंत्र में जन-भागीदारी का अवसर मात्र ही नहीं हैं, बल्कि देश की दशा-दिशा तय करने में आम आदमी के योगदान का भी परिचायक है। अधिकतम मतदान के लिए माहौल बनाने की आवश्यकता इसलिए है, क्योंकि देश के कुछ हिस्सों में मतदान प्रतिशत अपेक्षा से कहीं कम होता है। विडंबना यह है कि आमतौर पर कम प्रतिशत महानगरों में अधिक देखने को मिलता है। इसका कोई मतलब नहीं कि सरकारों अथवा राजनीतिक दलों के तौर-तरीकों की आलोचना तो बढ़-चढ़कर की जाए, लेकिन मतदान करने में उदासीनता दिखाई जाए। आमतौर पर मतदान न करने के पीछे यह तर्क अधिक सुनने को मिलता है कि मेरे अकेले के मत से क्या फर्क पड़ता है? एक तो यह तर्क सही नहीं, क्योंकि कई बार दो-चार मतों से भी हार-जीत होती है और दूसरे, अगर सभी यह सोचने लगें तो फिर लोकतंत्र कैसे सबल एवं सक्षम होगा? इस दृष्टि से प्रधानमंत्री मोदी का अधिकतम मतदान को प्रोत्साहन देने का उपक्रम एवं आह्वान एक क्रांतिकारी शुरूआत कही जा सकती है। इसका स्वागत हम इस सोच और संकल्प के साथ करें कि हमें अपने मतदान से आगामी आम चुनाव में भ्रष्टाचार, राजनीतिक अपराधीकरण एवं राजनीतिक विसंगतियों पर नियंत्रण करना है। अधिकतम मतदान के संकल्प से हमें मतदान का औसत प्रतिशत 55 से 90-95 प्रतिशत तक ले जाना चाहिए, ताकि इस लक्ष्य को हासिल करके हम भारतीय राजनीति की तस्वीर को नया रुख दे सके। मतदान करना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है और कर्तव्य भी है, लेकिन विडम्बना है हमारे देश की कि आजादी के 77 वर्षों बाद भी नागरिक लोकतंत्र की मजबूती के लिये निष्क्रिय है। ऐसा लगता है जमीन आजाद हुई है, जमीर तो आज भी कहीं, किसी के पास गिरवी रखा हुआ है। अधिकतम मतदान की दृष्टि से नरेन्द्र मोदी ने गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए एक अलख जगाई थी। अनिवार्य वोट के लिये कानून लागू करना ही होगा और इस पहल के लिये सभी दलों को बाध्य होना ही होगा, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र में यह नई जान फूंक सकती है। अब तक दुनिया के 32 देशों में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था है।

संक्षिप्त सामाचार

आरओ और एआरओ परीक्षा लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग

लखनऊ (संवाददाता)। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने आरओ एआरओ परीक्षा के पेपर लीक होने के संबंध में सीधे सबूत प्रस्तुत करते हुए परीक्षा निरस्त कराए जाने और इस संबंध में एफआईआर दर्ज कर सीबीआई जांच कराए जाने की मांग की है अपर मुख्य सचिव नियुक्ति तथा लोक सेवा आयोग के सचिव को भेजे अपने पत्र में उन्होंने कहा कि उन्हें जौनपुर के अटाला मस्जिद के निकट स्थित परीक्षा केंद्र के एक अभ्यर्थी ने बताया है कि उन्हें परीक्षा के द्वितीय पाली का प्रश्नपत्र स्वयं उसके मोबाइल नंबर पर समय 12.40 पीएम पर प्राप्त हुआ था। उस अभ्यर्थी ने दो अन्य लोगों के मोबाइल नंबर बताएं हैं जिनके माध्यम से होते हुए उन्हें यह प्रश्न पत्र प्राप्त हुआ। अभ्यर्थी ने बताया है कि स्वयं उसके क्लास में ही 8 से 10 अभ्यर्थियों के पास पहले से प्रश्नपत्र प्राप्त हो चुके थे। अमिताभ ठाकुर ने इसे अत्यंत महत्वपूर्ण साक्ष्य बताते हुए तत्काल परीक्षा निरस्त कर इस संबंध में एफआईआर दर्ज कराए जाने और सीबीआई जांच कराए जाने की मांग की है।

अयोध्या पहुंचे क्रॉस वोट करने वाले सपा विधायक

हमें अयोध्या आने से रोका गया था: अभय

लखनऊ (संवाददाता)। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले सपा विधायक रामलला का दर्शन करने अयोध्या पहुँचे। विधायक मनोज पांडेय ने कहा कि प्रभु श्रीराम के दर्शन का सौभाग्य आज हमें सपरिवार मिला है। भगवान राम के दर्शन से हमें अपने विधानसभा क्षेत्र, अपने जनपद और प्रदेश के तमाम लोग जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हैं, उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने की ताकत मिलेगी।उन्होंने सपा नेताओं के रामचरितमानस पर सवाल उठाने और बयानबाजी करने पर कहा कि जिन लोगों को सनातन और धार्मिक ग्रंथों का अपमान किया है उनका समूल नाश हो गया है। मैंने सपा में रहते हुए पार्टी के मंचों पर भी इसे उठाया है। पल्लवी पटेल के बयान पर कहा, उनका भी काम नहीं बन पाया है, उनको आत्ममंथन करने की जरूरत है कि कहां खड़ा होना चाहिए और कहां क्या बोलना चाहिए। सपा विधायक अभय सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें अयोध्या में रामलला का दर्शन करने से रोका गया था। हमें बहुत बुरा लगा। अभय सिंह ने कहा कि हम सभी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होना चाहते थे पर हमें इसके लिए निमंत्रण नहीं मिला। इस पर हमने विधानसभा अध्यक्ष से प्रार्थना की थी कि हमें अयोध्या ले चलें। सपा को छोड़कर सभी दलों के विधायक अयोध्या दर्शन करने पहुंचे थे। हमें रोका गया था। ये कष्ट देने वाला था।वहीं सपा अध्यख अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ये झूठ है किसी को भी अयोध्या जाने से नहीं रोका गया था।

आईएएस की नौकरी छोड़ करेंगे सियासत

सरकार ने मंजूर किया इस्तीफा, दिया वीआरएस

लखनऊ (संवाददाता)। केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद यूपी कैडर के 2011 बैच के आईएएस अधिकारी अभिषेक सिंह का इस्तीफा राज्य सरकार ने मंजूर कर लिया है। अभिषेक ने अक्टूबर 2023 में इस्तीफा दिया था और वीआरएस के लिए किया था आवेदन किया था। उनका इस्तीफा आज गुरूवार से प्रभावी माना जायेगा। आईएएस की नौकरी छोड़ने के बाद अभिषेक सिंह के राजनीति में जाने की अटकलें है। वे लोकसभा चुनाव में अपनी सियासी पारी का आगाज कर सकते हैं और जौनपुर से चुनाव लड़ सकते हैं।

राष्ट्रीय सामाजिक कार्य कर्ता संगठन राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन

⇨ हमारी सरकार किसानों को अपना दुश्मन मानती है: संदीप पाण्डेय

लखनऊ राष्ट्रीय सामाजिक कार्य कर्ता संगठन ने आज शहीद स्मारक, लखनऊ पर सोशलिस्ट किसान सभा राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे किसान आंदोलन और उसकी प्रमुख मांग कि न्यूनतम समर्थल मूल्य को कानूनी गारंटी के रूप में किसानों को उपलब्ध कराया जाए को अपना समर्थन किया। पंजाब के शम्भू व खनौरी सीमाओं पर जिस तरह से किसानों को हरयाणा व केन्द्र की पुलिस व सुरक्षा बलों का सामना करना पड़ रहा है ऐसा प्रतीत होता है जैसे अपने ही देश में हमारी सरकार किसानों को अपना दुश्मन मानती है। नरेन्द्र मोदी ने देश में जिन चार जातियों को गिनाया है उसमें किसान भी है और वे किसान को सम्मान निधि भी देते हैं। फिर भी किसान उनसे नाराज क्यों है और उसके साथ ऐसे सौतेला व्यवहार क्यों ? हम नौजवान किसान शुभकरन सिंह की पुलिस की गोली से मौत व सुरक्षा बलों द्वारा पंजाब की सीमा में घुस कर किसानों के ट्रैक्टरों को तोड़ने की कार्यवाही की निंदा करते हैं। सरकार और उसके नुमाइंदे यह जान लें कि वे जिस किसान और उसके उपकरणों का अपमान कर रहे हैं, ये वे ही है जो पूरे देश को खिलाते हैं, जिसमें वे भी शामिल हैं। पिछली बार 13 महीनों के लम्बे किसान आंदोलन के बाद सरकार ने तीन विवादास्पद कानून वापस लिए, थे और वायदा किया था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी के रूप में देंगे। किंतु अब सरकार अपने वायदे से मुकर गई है। सरकार में जो लोग निर्णय ले सकते हैं वे वार्ता में ही शामिल नहीं हैं। और कनिष्ठ लोग जो वार्ता कर रहे हैं वे कोई निर्णय नहीं ले सकते। यानी सरकार खुलकर किसानों का माखौल उड़ा रही है और किसान की मजबूरी है कि उसे सरकार से वार्ता करनी ही होगी। सोशलिस्ट किसान सभा सरकार को चेतावनी देती हैं कि यदि उसने किसानों की प्रमुख मांग को नहीं माना तो उ.प्र. में जगह जगह प्रदर्शन शुरू कर दिए जाएंगे। इस ओसर पर गौतम राणे सागर (सनोधन संरक्षण मंच के राष्ट्रीय संयोजक), रोशन एक करण के अध्यक्ष रोशन जहां, रोशन एक कारण के उपाध्यक्ष सिस्टर फरीदा, राष्ट्रीय कार्य कर्ता संगठन के संयोजक मुहम्मद अफाक, जियाउल्लाह सिद्दीकी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जिला .अध्यक्ष डॉ. आफताब, उमताना संघर्ष समिति के अध्यक्ष मुर्तजा अली, मुहम्मद अहमद, इंडियन नेशनल लीग के प्रवक्ता मौलाना इरशाद अहमद सिद्दीकी, सैयद अली मुशीर, राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के राष्ट्रीय संयोजक पीसी कारेल, राम लोट, राम सत जेसवारा, राम बच, बसंत लाल बर्मा , सलीम खान , सिराज खान, अनिल कुमार मिश्र, कमलेश पाण्डेय, सचेन्द्र परताप यादो, शारुख खान, जगरूप परसाद, मुन्नी देवी, परवीन बानो, अशोक चोरस्या, राम शंकर, गीता देवी, जुबैर अहमद मोजूद रहे।

अकबरनगर में कबाड़ियों का मोलभाव

100 करोड़ की जमीन पर बनी दुकानों के सामान का हजारों में कर रहे सौदा

लखनऊ (संवाददाता)। अकबरनगर में कबाड़ियों ने मोलभाव शुरू कर दिया है। 100 करोड़ की जमीन पर बनी 24 दुकानों पर कबाड़ी मौजूद हैं। यहीं पर दुकानें तोड़ी गई हैं। इस दौरान बचे सामान का कुछ हजार रूपए में सौदा कर रहे। कार्रवाई के बाद से आस-पास सन्नाटा पसरा हुआ है। बड़ी संख्या में कबाड़ी सामान ढो कर ले जा रहे ।ताजमहल और सम्राट फर्नीचर सहित 24 दुकानों तो तोड़ा गया है। इसके बाद से यहां पर सुबह से आस-पास के कबाड़ी इकट्ठा हो गए हैं। इसमें दुकानों के सरिया का ठेका दस से पंद्रह हजार तक में हुआ है। कबाड़ी मुन्ना ने बताया कि 30 रुपए प्रति किलो सरिया की दर है। इसे साढ़े तीन हजार रूपए प्रति क्विंटल बेचेंगे। एक दुकान से 10 क्विंटल सरिया निकलने का अनुमान है। इसके लिए दुकानदारों को नगदी देकर ही अंदर जा रहे। जितना माल निकल रहा उसका आधा दुकानदार और आधा कबाड़ी वाले ले रहे। दुकानों से सरिया और लोहे का सामान निकाल रहे कबाड़ी आपस में0 ही भिड़ गए। मौके पर मौजूद पुलिस ने बहस और धक्का मुक्की की रहे कबाड़ियों को भगा दिया। अलग-अलग 24 दुकानों पर 100 से अधिक कबाड़ी पहुंचे हैं, जो सुबह से ही सरिया निकाल कर ले जा रहे। इस दौरान कबाड़ को एक जगह इकट्ठा कर रहे। उसके बाद पिकप, ठेला और ई रिक्शा से लेकर बेचने जा रहे हैं। बिजली नहीं होने पर जनरेटर चलाकर सरिया की कटाई हो रही है। एलडीए की टीम अवैध निर्माण का सर्वे करने के लिए मौके पर पहुंची है।

अधिवक्ताओं से मारपीट, 6 उप निरीक्षक समेत 18 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज

लखनऊ (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के विभूति खंड क्षेत्र में हाल ही में कुछ अधिवक्ताओं से मारपीट करने और साजिशन मुकदमे में फंसाने के आरोप में छह उप निरीक्षक समेत 18 पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। सूत्रों ने बताया कि बुधवार देर रात विभूति खंड थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। 23 फरवरी की रात विभूति खंड स्थित समिट बिल्डिंगश में खाना खाने गए अधिवक्ता अभिषेक सिंह चैहान, रोहित रावत, अभिषेक पांडे, मुकुल सिंह और उनके कुछ अन्य साथियों को, दो पक्षों के बीच झगड़े की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे उपनिरीक्षक राहुल बालियान और उनके साथ ही पुलिसकर्मियों ने बुरी तरह पीटा। सूत्रों ने बताया कि इससे अधिवक्ता रोहित रावत का हाथ टूट गया और अभिषेक चैहान की नाक की हड्डी टूट गई। रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया है कि पुलिस ने पीड़ित अधिवक्ताओं को रातभर थाने में बैठा कर उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया और समिट बिल्डिंगश में दो पक्षों के बीच हुए झगड़े के मामले में साजिशन इन अधिवक्ताओं को भी अभियुक्त बना दिया।इस मामले में उप निरीक्षक राहुल बालियान, जसीम रजा, प्रमोद कुमार सिंह, फूलचंद, रितेश दुबे और विनय गुप्ता तथा सिपाही ए. के. पांडे के खिलाफ नामजद तथा 10-12 अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147 (उपद्रव करना), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 325 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना) और 504 (धमकाना) के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।

साड़ी पहन दौड़ती महिलाओ को देख लोग दंग

नारी शक्ति की गूँज और भारतीय परिधान की खूबसूरत झलक: कौशल

साड़ी पहनकर महिलाओं ने मैराथन में किया शानदार प्रदर्शन

लखनऊ (संवाददाता)। सांसद खेल स्पर्धा के तहत मोहनलालगंज लोकसभा की साड़ी युक्त सेमी क्वार्टर मैराथन दौड़ कार्यक्रम का भव्य आयोजन केडी सिंह बाबू स्टेडियम, लखनऊ में संपन्न हुआ। 5 किलोमीटर की दौड़ थी जिसमें हजारों महिलाओं ने साड़ी पहनकर दौड़लगाई। साड़ी में दौड़ती महिलाओं में नारी शक्ति की गूँज और भारतीय परिधान की खूबसूरत झलक दिखी। मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र मोहनलालगंज के अंतर्गत सांसद खेल स्पर्धा के तहत लोकसभा की पांचो विधानसभा में विभिन्न खेल आयोजन और हर विधानसभा स्तर पर साड़ी युक्त महिला सेमी क्वार्टरमैराथन दौड़ का आयोजन होने के बाद लोकसभा स्तर पर फाइनल के तौर पर ये साड़ी युक्त महिला सेमी क्वार्टर मैराथन दौड़ का भव्य आयोजन केडी सिंह बाबू स्टेडियम में हुआ जोकि अद्भुत, अकल्पनीय, शानदार रहा। सांसद खेल स्पर्धा के तहत 29 फरवरी, बृहस्पतिवार को हुई इस साड़ी युक्त महिला सेमी क्वार्टर मैराथन का इसके आयोजक केंद्रीय राज्यमंत्री व सांसद कौशल किशोर ने शुभारंभ किया जिसके बाद साड़ी पहनकर प्रतिभाग कर रही हजारों महिलाओं ने उत्साह और जोश के साथ दौड़ लगाई। महिलाओं ने भारतीय संस्कृति और भारतीय परिधान के साथ साड़ी पहनकर जो दौड़ लगाई उसे देखकर सभी दंग रह गए।

सांसद खेल स्पर्धा के अंतर्गत मोहनलालगंज लोकसभा में सांसद कौशल किशोर के नेतृत्व में सभी विधानसभाओं में महिलाओं की खेल में भागीदारी बढ़ाने और खासकर घरेलू महिलाएं जो ज्यादा घर से बाहर नहीं निकल पाती उनके लिए भी खेलों का आयोजन हो और वह भी खेल में आगे बढ़े, दबी छिपी प्रतिभाओं को ढूंढने के लिए ये आयोजन किया जा रहा ऐसा केंद्रीय राज्यमंत्री व सांसद कौशल किशोर ने बताया। कौशल किशोर ने कहा कि नारी सिर्फ परिवार के लिए ही नही बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़कर समाज और देश के विकास में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र में सांसद खेल स्पर्धा के तहत सभी विधानसभाओं में हुई साड़ी युक्त सेमी क्वार्टर मैराथन और आज की दौड़ महिलाओं के द्वारा अपनी भारतीय संस्कृति को संजोते हुए खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत स्वच्छ और स्वस्थ भारत बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं, नारी, युवा, गरीब, किसान विकसित भारत के चार स्तंभ हैं। विकसित और आत्मनिर्भर भारत बनाने में महिलाओ की भागीदारी अहम है इसलिए सभी क्षेत्रों में महिलाओं को आगे आकर विकसित भारत बनाने में अपना सफल योगदान देना है। उन्होंने कहा कि इस तरह की दौड़ कराने का मुख्य उद्देश्य दबी छिपी प्रतिभाओं को मौका देना, खेल में महिलाओं की रूचि बढ़ाना, उन्हें और अधिक प्रतिभावान बनाना है, जिससे ये महिलाएं अपने परिधान अपनी संस्कृति को संजोते हुए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचकर अपनी खेल प्रतिभा को दिखा सके और हमारे क्षेत्र, प्रदेश और देश का नाम रोशन करें। मोहनलालगंज लोकसभा की इस साड़ी युक्त सेमी क्वार्टर मैराथन दौड़ में मोहनलालगंज लोकसभा की ही निवास करने वाली 18 वर्ष की ऊपर की महिलाओ ने प्रतिभाग किया जिसमे बख्तौरी खेड़ा निवासी आसमां ने प्रथम और संगीता ने द्वितीय तथा कुर्सी हिंडोरा निवासी सविता ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।प्रथम पुरस्कार के रूप में 51 हजार ,द्वितीय 41 हजार तृतीय पुरस्कार के रूप में 31 हजार रुपए धनराशि की चेक व प्रमाणपत्र केंद्रीय राज्यमंत्री कौशल किशोर द्वारा वितरित किया गया।

कर्मचारियों की समस्याओं का होगा निदान, एसीएस नियुक्ति ने किया आश्वस्त

लखनऊ (संवाददाता)। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की मांगों पर एसीएस नियुक्ति एव कार्मिक डा देवेश चतुवेर्दी के साथ हुई बैठक हुई में सार्थक निर्णय लिये गये।राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री अतुल मिश्रा ने बताया कि बैठक में वीपी मिश्र अध्यक्ष कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा ,सुरेश कुमार रावत अध्यक्ष एवं गिरीश चन्द्र मिश्रा वरिष्ठ उपाध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उपस्थित थे। बैठक में निर्णय लिया गया कि डिप्लोमा फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन एवं ऑप्टोमेट्रिस्ट की वेतन विसंगतियों पर चुनाव से पूर्व निर्णय कराए जाएंगे तथा केंद्र की भांति पदनाम परिवर्तन भी कर दिया जाएगा। आउटसोर्सिंग ,संविदा कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन सेवा नियमावली पर एक माह में निर्णय कराया जाएगा। सिंचाई विभाग के नलकूप चालक,सींचपाल, सींच पर्यवेक्षक, जिलेदार, ट्यूबवेल टेक्नीशियन संवर्ग के नियमावली उनकी देखरेख में एक माह में जारी करा दी जाएगी। रोडवेज कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की बकाया किस्तों का भुगतान करने का आदेश कर दिया गया है, शेष मांगों पर वित्त विभाग एवं परिवहन के प्रमुख सचिव के साथ जल्द बैठक करके निर्णय कर दिया जाएगा। भारत सरकार की भाँति एल टी सी पर जाने पर 10 दिन का अवकाश नकदी कारण देने पर वित्त विभाग से परामर्श करके निर्णय किया जाएगा। कैशलेस इलाज में आ रही दिक्कतों को तत्काल दूर किया जाएगा ।कर्मचारियों के लिए अलग काउंटर व इलाज की व्यवस्था की जाएगी। बायोमैट्रिक अटेंडेंस में संगठनों के पदाधिकारियों को मीटिंग में व संगठन कार्य के लिए जाने पर विशेष छूट दी जाएगी। मान्यता प्राप्त सेवा संघों,महासंघों के पदाधिकारी को विशेष आकस्मिक अवकाश की सुविधा में वृद्धि करने पर निर्णय किया जाएगा। बैठक के अंत में अपर मुख्य सचिव कार्मिक द्वारा सार्थक निर्णय करने के लिए उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आशा व्यक्त की कि बैठक में बनी सहमति पर चुनाव से पूर्ण निर्णय करायेंगे।

विश्वकर्मा समाज को अधिकार पाने के लिए एकजुट होना पड़ेगा: राम आसरे

लखनऊ (संवाददाता)। आजमगढ़ के दुवार्सा धाम में भगवान विश्वकर्मा मन्दिर का स्थापना दिवस मनाया गया जिसमें बड़ी संख्या में विश्वकर्मा समाज के लोग शामिल हुए। सम्मेलन में मुख्य अतिथि पूर्व मन्त्री राम आसरेविश्वकर्मा रहे। इस अवसर पर राम आसरे विश्वकर्मा ने बताया कि विश्वकर्मा मन्दिर के सामनेविश्वकर्मा घाट का निर्माण मैंने मन्त्री रहते हुए सरकार की निधि से कराया था। मौका मिला तो विश्वकर्मा धर्मशाला तथा मन्दिर को और सुन्दर बनायेंगे। विश्वकर्मा समाज को अपने अधिकार लेने के लिये एकजुट करने का आान किया।

सपा सरकार में विश्वकर्मा

लखनऊ आ जाएं अधिकारी जांच के लिए तैयार हूं

○ सीबीआई के समन पर दिल्ली नहीं पहुंचे अखिलेश यादव

लखनऊ (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज (29 फरवरी) सीबीआई के सामने पेश नहीं होंगे। केंद्रीय एजेंसी ने खनन घोटाला मामले में अखिलेश यादव को तलब किया था। अखिलेश यादव का कहना है कि मैं जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हूं लेकिन अधिकारी लखनऊ आ जाएं। यह बात उन्होंने दिल्ली न जाने के बाद कही है। आपको बता दें कि सीबीआई ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को बतौर गवाह बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस भेजा था। अखिलेश यादव को आज ही दिल्ली आकर अपना बयान दर्ज कराना था, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सपा प्रमुख आज सीबीआई के सामने पेश नहीं होंगे। मिली जानकारी के मुताबिक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने मामला दर्ज करने के 5 साल बाद अवैध खनन मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बृहस्पतिवार को पूछताछ के लिए एक गवाह के रूप में बुलाया है। अधिकारियों ने बताया कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 160 के तहत जारी नोटिस में एजेंसी ने उन्हें 2019 में दर्ज मामले के संबंध में 29 फरवरी को पेश होने के लिए कहा था।

राजपाठ नहीं मिला तो मैं होली नहीं मनाऊंगा: राजभर

हाथी के दिखाने के दांत और होते और खाने के और

लखनऊ (संवाददाता)। यूपी में लोकसभा चुनाव 2024 खातिर सभी पार्टियां तैयारी में जुटी है। बयानबाजी का भी दौर जारी है। इसके बीच सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का गुरुवार को बड़ा बयान सामने आया है।उन्होंने कहा है कि यदि राजपाठ नहीं मिला तो मैं होली नहीं मनाऊंगा। राजभर ने कहा, भर जाति का राज पाठ होली के दिन ही गया था, इसलिए मैं होली नहीं मनाऊंगा। ओम प्रकाश राजभर से मंत्री पद को लेकर सवाल किया, राजभर ने कहा कि आप देखते जाइए क्या होता है? हम तो होली मनाते नहीं है, क्योंकि हमने इतिहास पढ़ा है कि भर जाति का राजपाट होली के दिन ही छीना गया था। जब इस देश में 585 राजा होते थे, तो देश में 165 अकेले भर जाति के राजा थे। ये इतना मस्त हो गए कि होली के दिन खिला पिलाकर राजपाट छीन लिया गया। इसलिए जब तक मैं राजपाट नहीं ले लेता हूं, तब तक मैं होली नहीं मनाऊंगा। ओम प्रकाश राजभर बीते साल जुलाई, 2023 में एनडीए में शामिल हुए थे, राजभर को एनडीए में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शामिल करवाया था। इसके बाद लगातार राजभर दावा करते हुए दिखायी दिए कि उन्हे मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। लेकिन अभी तक नतीजा शिफर। मंत्री न बनाए जाने पर राजभर का दर्द एक बार फिर सामने आया। राजभर ने कहा कि लोकतंत्र में प्रदेश का राजा मुख्यमंत्री और देश का राजा प्रधानमंत्री होता हैं। हम तो हमेशा से ही वंचितों को जगाने का काम करते रहते हैं। सुभासपा प्रमुख ने इस दौरान राज्यसभा चुनाव में सपा विधायकों द्वारा की गई क्रॉस वोटिंग पर भी तंज कसा और कहा कि ष्आपने देखा होगा कि उनका दाहिना हाथ कहे जाने वाले मनोज पांडे भी उधर चले गए।

राजधानी से पांच जिलों के लिए कल से शुरू होगी विमान सेवा, शेड्यूल जारी

लखनऊ (संवाददाता)। चैधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से मुरादाबाद, चित्रकूट, श्रावस्ती, अलीगढ़ और आजमगढ़ के लिए विमान सेवाएं 2 मार्च से शुरू होंगी। फ्लाईबिग एयरलाइंस ने इसका शेड्यूल जारी कर दिया है। राज्य सरकार की पहल पर उड़ान योजना के तहत पांच शहरों के लिए विमान सेवाएं शुरू होनी है। लखनऊ से श्रावस्ती, चित्रकूट, अलीगढ़, आजमगढ़ और मुरादाबाद का सफर आधे से डेढ़ घंटे में पूरा हो जाएगा। विमान सेवा फ्लाईबिग एयरलाइंस की ओर से ये सेवाएं 19 सीटर विमान से दी जाएंगी। पांच जिलों के लिए किराया क्या होगा इसकी जानकारी नहीं दी गई है। सूत्रों की मानें तो दो से ढाई हजार के बीच किराया हो सकता है। लखनऊ से श्रावस्ती के लिए विमान संख्या एस 9337 दोपहर में 3.15 बजे उड़ान भरेगी और शाम 4 बजे पहुंचेगी। जबकि श्रावस्ती से विमान संख्या एस9 340 शाम 4.20 पर उड़ान भरकर 5.10 पर लखनऊ पहुंचेगी। लखनऊ से श्रावस्ती के लिए उड़ान सेवा प्रतिदिन रहेगी। जबकि आजमगढ़, चित्रकूट, अलीगढ़ और मुरादाबाद के लिए विमान सेवा सप्ताह में छह दिन होगी। लखनऊ से मुरादाबाद के लिए विमान संख्या एस 9 327 सुबह 8.45, लखनऊ से अलीगढ़ के लिए विमान संख्या एस 9 315 दोपहर 12.10, लखनऊ से आजमगढ़ के लिए विमान संख्या एस 9 331 सुबह 8.55 और लखनऊ से चित्रकूट के लिए विमान संख्या एस 9 333 दोपहर 11.40 पर उड़ान भरेगी।

अवनीश अवस्थी का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाया गया

लखनऊ (संवाददाता)। सीएम योगी आदित्यनाथ के सलाहकार अवनीश अवस्थी को तीसरी बार सेवा विस्तार मिला है। सेवानिवृत्त आईएएस अवनीश अवस्थी का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ाया गया है। शासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि मुख्यमंत्री को उनके प्रशासनिक कार्यों में सलाह देने के लिए अवनीश अवस्थी को 28 फरवरी 2025 तक तैनात किया गया है। अवनीश अवस्थी 31 अगस्त 2022 को रिटायर हुए थे। इसके बाद अस्थाई रूप से तैनाती के लिए उनके लिए स्पेशल नया पद बनाया गया था। वहीं पहली बार अस्थाई कार्यकाल खत्म होने पर राज्यपाल ने फिर 2023 से अवनीश अवस्थी को सलाहकार के रूप में 29 फरवरी 2024 तक तैनाती की स्वीकृति दी थी। अब एक बार फिर इसलिए उनका कार्यकाल एक मार्च से 2024 से 28 फरवरी 2025 तक बढ़ाया गया था। अवनीश अवस्थी मुख्यमंत्री के सबसे भरोसेमंद अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं।अवनीश अवस्थी साल 1987 बैच के आईएएस अफसर हैं। वह 31 अगस्त 2022 को सेवानिवृत्त हुए थे। उनके नाम सबसे लंबे समय तक यूपी का गृह विभाग संभालने का रिकॉर्ड भी है। यूपी में 2017 में भाजपा की सरकार बनने के बाद अवनीश अवस्थी को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस प्रदेश में बुला लिया था। उन्हें सूचना विभाग के साथ यूपीडा सीईओ और गृहव विभाग जैसी अहम जिम्मेदारियां दी गईं थी। योगी सरकार के हर प्रशासनिक कार्य में उनकी भूमिका काफी अहम रही है। कोरोना काल में आक्सीजन की व्यवस्था कराने और प्लांट लगवाने में अधिकारी के तौर पर उन्होंने काफी मेहनत की थी।

अखिलेश को सीबीआई की नोटिस पर शुरू हुई सियासत

○ एक्टिव हो जाओ, भैया जी को मिली नोटिस: रालोद

○ इंडिया गठबंधन में होने के कारण मिली है नोटिस: कांग्रेस

लखनऊ (संवाददाता)। 29 फरवरी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को एक मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई द्वारा नोटिस दिये जाने के बाद राष्ट्रीय लोकदल ने प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस का भी बयान आया है। सीबीआई की नोटिस को लेकर सियासी बयानबाजी शुरू है। रालोद के रोहित अग्रवाल ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर प्रतिक्रिया दी है। सोशलमीडिया साइट एक्स पर रोहित अग्रवाल ने कहा कि जवानी कुर्बान गैंग एक्टिवेट हो जाओ, भैया जी को नोटिस आया है। दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि बीजेपी यह काम अखिलेश यादव को घेरने के लिए कर रही है। मीडिया से मुखातिब अजय राय ने कहा कि अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन का मजबूत हिस्सा है,इसलिए बीजेपी उन्हें पुराने मामलों के जरिए घेरने की कोशिश कर रही है। सीबीआई सूत्र ने कहा कि सीबीआई ने उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव को रेत खनन से संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा संदर्भित एक मामले में एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा है। उन्हें कल 29 फरवरी को दिल्ली में सीबीआई के समक्ष गवाह के रूप में जांच में शामिल होने के लिए कहा गया है। कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा, अखिलेश यादव को इंडिया गठबंधन में होने की वजह से सीबीआई की नोटिस भेज दिया, मतलब साफ हैं भाजपा डर गई।

बंगाली फिल्म बोहूरूपी में देखने को मिलेगी अबीर और रिताभरी की जादुई केमिस्ट्री

बंगाली एक्ट्रेस रिताभरी चक्रवर्ती अपकमिंग बंगाली फिल्म बोहूरूपी में अभिनय करने के लिए तैयार हैं। यह फिल्म निर्देशक जोड़ी नंदिता रॉय और शिबोप्रसाद मुखर्जी द्वारा निर्देशित है। फिल्म में खुद शिबोप्रसाद मुखर्जी भी हैं। यह फिल्म 1998 और 2005 के बीच की पृष्ठभूमि में एक वास्तविक कहानी को जीवंत करने का वादा करती है। शिबोप्रसाद ने एक बयान में कहा, हमने 2011 में फिल्म की योजना बनाना शुरू कर दिया था। मुक्तोधारा के ठीक बाद, हम यह फिल्म बनाना चाहते थे, जो 1998 और 2005 के बीच की समयरेखा को दशार्ती है। बोहूरूपी उस समय के आसपास हुई घटनाओं की एक श्रृंखला पर आधारित है। स्क्रिप्ट के माध्यम से हमने उस युग का वर्णन करने का प्रयास किया है। उन्होंने आगे कहा, हम वास्तविक पात्रों को प्रदर्शित करने वाली फिल्म के साथ-साथ एक डॉक्यूमेंट्री भी जारी करने की योजना बना रहे हैं। पिछले साल की सुपरहिट फिल्म फाटाफटी में अबीर और रिताभरी की जादुई केमिस्ट्री इसमें भी नजर आएगी। अबीर ने कहा, इस साल मुझे दो अलग-अलग भूमिकाएं सौंपने के लिए मैं नंदिता दी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आमार बॉस के बाद, मैं बोहूरूपी में एक बिल्कुल अलग किरदार को जीवंत करने के लिए रोमांचित हूं। फिल्म 12 मार्च को फ्लोर पर जाएगी। 78 स्थानों पर 40 दिनों तक इसकी शूटिंग की जाएगी।

हीरो नहीं बल्कि खतरनाक विलेन को दिल दे बैठीं ये खूबसूरत हसीनाएं

बेशक फिल्मों के हीरो-हीरोइन के असल जिंदगी में विवाह बंधन में बंधने की खबरें आती रहती हैं लेकिन ऐसी भी एक्ट्रेसेस रही हैं जिन्होंने असल जिंदगी में फिल्म के विलेन के साथ लिए सात फेरे दूरदर्शन की टीवी शो सुरभि से अपने करियर की शुरूआत करने वाली एक्ट्रेस रेणुका शहाणे हिंदी और मराठी फिल्मों में काम कर चुकी हैं पहले विजय केनकरे नाम के शख्स से शादी रचाई, लेकिन दोनों की शादी लंबे समय तक नहीं चल पाई। इसके बाद रेणुका का दिल बॉलीवुड के खूंखार विलेन आशुतोष राणा पर आया, 2001 में दोनों ने शादी की और आज हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। छोटे पर्दे पर अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेर चुकी एक्ट्रेस निवेदिता भट्टाचार्य का दिल भी बॉलीवुड के विलेन रह चुके केके मेनन पर आया। दोनों ने शादी की और आज अपनी लाइफ में दोनों खुश है। बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस पूजा बत्रा भी अपनी लव लाइफ को लेकर खूब सुर्खियों में रही है उनका दिल फिल्मों में विलेन का किरदार निभा चुके नवाब शाह पर आया, 2019 में दोनों ने शादी भी कीया। शिवांगी कोल्हापुरे 80 की दौर की एक फेमस एक्ट्रेस रही हैं, जिन्होंने अमिताभ बच्चन से लेकर मिथुन चक्रवर्ती के साथ काम किया. लेकिन जीवनसाथी के रूप में इन्होंने बॉलीवुड के सबसे बड़े विलेन यानी कि शक्ति कपूर को चुना।

राज कुंद्रा का छलका दर्द, कहा मेरे जेल जाने पर परिवार को सुनाई गई खरी खोटी

बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को साल 2021 में एडल्ट फिल्म बनाने के मामले में जेल जाना पड़ा था। अपने उस कठिन समय के बारे में राज कुंद्रा ने कई बार बात की लेकिन पहली बार उन्होंने खुलासा किया कि जब वो जेल में थे तो बाहर उनके परिवार का कैसा हाल था।साल 2021 शिल्पा शेट्टी के लिए एक बुरे सपने जैसा था। उनके पति राज कुंद्रा को एडल्ट फिल्म बनाने और अपने ऐप पर अपलोड करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, इस मामले में उन्हें दो महीने बाद 21 सितंबर को बेल मिल गयी थी। जेल से बाहर आने के बाद राज कुंद्रा ने मीडिया से दूरी बनायी रखी और वो चेहरे पर अलग अलग तरह के मास्क लगाकर स्पॉट होते थे।राज कुंद्रा ने अपने उस सबसे मुश्किल दौर पर एक फिल्म भी बनायी, दुनिया को अपनी कहानी बताने के लिए उन्होनें फिल्म यूटी 69 रिलीज की थी। शिल्पा शेट्टी के पति ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर तो कई बार बात की, लेकिन पहली बार उन्होंने बताया कि उनके बेटे वियान कुंद्रा का हाल उस समय कैसा था। हिन्दुस्तान टाइम्स से बातचीत के दौरान राज कुंद्रा ने बेटे वियान के टूटने के दर्द के बारे में बात करते हुए कहा कि शुरूआत में तो मां शिल्पा शेट्टी ने अपने बेटे को संभाल लिया, लेकिन जब काफी दिनों तक राज घर नहीं आए, तो वियान ने उनसे सवाल करना शुरू कर दिया।वियान ने पूछा क्या हुआ, तो शिल्पा ने बोला कि आपके पापा को कई सवालों के जवाब देने हैं,जैसे ही वह दे देंगे वापस आ जाएंगे। शिल्पा ने उसके स्कूल में किसी से बातचीत की थी, पता नहीं वहां पैरेंट अपने बच्चों को क्या कह रहे थे। वियान बहुत ही स्ट्रांग बच्चा है। जब मैं जेल में था, तो उसने कुछ ड्रॉ किया और उसे लेटर के साथ भेजा। उसने लिखा था, पापा आपकी बहुत याद आ रही है,आप अपना काम खत्म करके जल्दी से आ जाओ। राज ने यह भी बताया कि इन सबका खामियाजा मेरी पत्नी शिल्पा शेट्टी को भुगतना पड़ा था। शिल्पा को कई कॉन्ट्रैक्ट और टेलीविजन काम गंवाने पड़े थे। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने एक सेलिब्रिटी से शादी की है। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो मुझे नहीं लगता है कि इसका आधा भी नुकसान होता। मुझे लगता है कि वे मुझ पर नहीं, बल्कि मेरी पत्नी और बच्चों पर हमला कर रहे थे।

अनिल कपूर ने पीएम मोदी के संदेश को आगे बढ़ाया, लोगों से वोट की शक्ति का प्रयोग करने का आग्रह किया

बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर ने देश के मतदाताओं से आगे आने और मतदान की अपनी शक्ति का प्रयोग करने का आग्रह किया है। 2024 के लोकसभा चुनाव करीब आने के साथ, देश सबसे बड़ी चुनावी कवायद की तैयारी कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मतदान की शक्ति का संदेश फैलाने के लिए सभी क्षेत्रों के लोगों को आमंत्रित किया। अनिल कपूर ने अपने एक्स अकाउंट पर प्रधानमंत्री मोदी के संदेश को प्रचारित किया और उनका संदेश शेयर किया। पीएम मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, आइए हम अपनी चुनावी प्रक्रिया को और अधिक सहभागी बनाएं। मैं जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों से आान करता हूं कि वे पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं के बीच अपने-अपने अंदाज में संदेश फैलाएं। अनिल कपूर ने प्रधानमंत्री मोदी की पोस्ट का हवाला देते हुए लिखा, मतदान से बड़ा कोई नागरिक कर्तव्य नहीं है। मैं हमारे देश के सभी पात्र नागरिकों से आग्रह करता हूं कि वे सोच-समझकर फैसला लें और मतदान करके अपने अधिकार और शक्ति का प्रयोग करें।

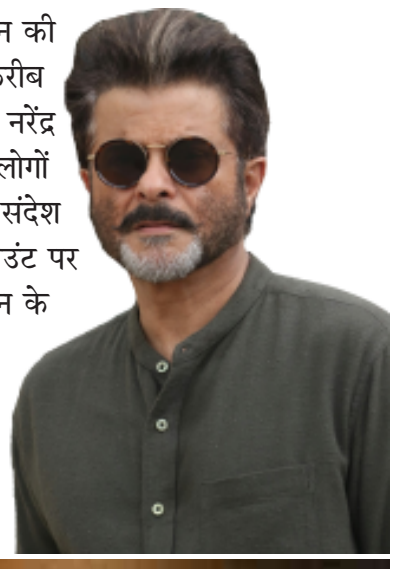

शो में पहली बार एक्शन सीक्वेंस करना मेरे लिए एक खास अनुभव: रजत वर्मा

टीवी शो दहेज दासी में जय के किरदार में नजर आने वाले एक्टर रजत वर्मा ने अपने किरदार को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि शो में पहली बार एक्शन सीक्वेंस करना मेरे लिए एक अनोखा अनुभव रहा। शो के बारे में बात करते हुए रजत ने कहा, इसमें मुझे पहली बार एक्शन सीक्वेंस करने का मौका मिला। यह मेरे लिए बहुत ही खास अनुभव रहा। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया था। मेरी ओर से हुई एक गलती के कारण मेरे अंगूठे में चोट भी लग गई थी, लेकिन यह मजेदार और अद्भुत अनुभव था। उन्होंने कहा, मैंने अपने किरदार के लिए बहुत सारी तैयारियां की थी, मुझे अपने व्यक्तित्व को एक राजपूत परिवार का हिस्सा होने जैसा दिखाना था। उन्होंने कहा कि उनका किरदार राजस्थान के एक छोटे से गांव के युवा कुंवर जय सिंह के बारे में है, जिसे उनकी मां ने पाला है। उन्होंने कहा, वह बहुत भावुक है क्योंकि उसका पालन-पोषण एक महिला ने किया है। बचपन में उसे पढ़ने के लिए दिल्ली भेजा गया था इसलिए वे संस्कृति और परंपराओं से दूर था और आधुनिक दृष्टिकोण रखते था। जब वह वापस आता है तो उसे संस्कृति और परंपराओं के बारे में पता चलता है। वह विद्रोही किस्म का है और वह रीति-रिवाजों को चुनौती देता है। यह पूछे जाने पर कि उन्हें किरदार से क्या जोड़ता है, रजत ने कहा, एक चीज जो मुझे किरदार से जोड़ती है, वह यह है कि मैं भी अपने किरदार की तरह ही विद्रोही हूं, जो चीजें लोगों को चोट पहुंचाती हैं और समाज के लिए गलत होती है, मैं उन चीजों से लड़ता हूं। शो में सयंतनी घोष भी हैं, जो विंध्या देवी की भूमिका निभाती हैं। यह नजारा टीवी पर प्रसारित होता है।

बीसीसीआई के वार्षिक अनुबंध से अय्यर-किशन बाहर

सिराज-गिल को इनाम, रिंकू को भी मिली जगह

उत्तर प्रदेश के बाएं हाथ के बल्लेबाज रिंकू सिंह को ग्रेड-सी में जगह मिली है। ए प्लस ग्रेड में कप्तान रोहित शर्मा के अलावा विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रवींद्र जडेजा हैं।

एजेंसी

नई दिल्ली। बीसीसीआई ने वार्षिक अनुबंध की सूची जारी कर दी है। सीजन 2023-24 के लिए जारी की गई इस लिस्ट में श्रेयस अय्यर और ईशान किशन का नाम नहीं है। दोनों खिलाड़ियों ने घरेलू क्रिकेट में हिस्सा नहीं लिया था। इस कारण बोर्ड नाराज था। उसका असर अनुबंध सूची में देखने को मिला। बीसीसीआई ने अपने बयान में कहा कि अय्यर और ईशान को वार्षिक अनुबंध नहीं दिया गया है। उत्तर प्रदेश के बाएं हाथ के बल्लेबाज रिंकू सिंह को ग्रेड-सी में जगह मिली है। ए प्लस ग्रेड में कप्तान रोहित शर्मा के अलावा विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रवींद्र जडेजा हैं।बीसीसीआई ने इस साल 30 खिलाड़ियों को अनुबंध दिया है। यह एक अक्तूबर 2023 से 30 सितंबर 2024 तक के लिए है। बोर्ड ने इस बार एक नई परंपरा जारी की है। उसने तेज गेंदबाजी अनुबंध भी अलग से दिया है। इस लिस्ट में आकाश दीप, विजयकुमार वैश्यक, उमरान मलिक, यश दयाल और विद्वथ कावेरप्पा शामिल हैं।

खिलाड़ियों को कितने पैसे मिलते हैं?

ग्रेड ए प्लस में शामिल खिलाड़ियों को सालाना सात करोड़ रुपये मिलते हैं। ए ग्रेड में पांच और बी ग्रेड में तीन करोड़ रुपये मिलते हैं। सबसे निचले सी ग्रेड में शामिल किए गए खिलाड़ियों को एक-एक करोड़ रुपये दिए जाते हैं।

बीसीसीआई ने अपने बयान में क्या कहा?

इसके अलावा जो खिलाड़ी इस अवधि के भीतर न्यूनतम तीन टेस्ट या आठ वनडे या 10 टी20 खेलने के मानदंडों को पूरा करते हैं, उन्हें स्वचालित रूप से आनुपातिक आधार पर ग्रेड सी में शामिल किया जाएगा। उदाहरण के लिए- ध्रुव जुरेल और सरफराज खान ने अब तक दो टेस्ट मैच खेले हैं अगर इंग्लैंड के खिलाफ चल रही सीरीज के पांचवें टेस्ट में भाग लेते हैं, तो उन्हें ग्रेड सी में शामिल किया जाएगा। बीसीसीआई ने सिफारिश की है कि सभी एथलीट उस अवधि के दौरान घरेलू क्रिकेट में भाग लेने को प्राथमिकता दें जब वे राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हों।

किसे फायदा, किसे नुकसान?

राहुल, शुभमन गिल और सिराज को ग्रेड ए में पदोन्नत किया गया है। जबकि सड़क दुर्घटना के कारण एक साल से ज्यादा समय से नहीं खेलने वाले ऋषभ पंत को ग्रेड बी में जगह मिली है।

पीएम सूर्य के घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी

75,021 करोड़ की लागत से एक करोड़ घरों पर लगेगा सोलर पैनल

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 75,021 करोड़ रुपये के खर्च के साथ एक करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर लगाने के लिए पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी, 2024 को इस योजना की शुरूआत की थी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के इस फैसले की जानकारी दी है।केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज पीएम मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई। इसी बैठक के दौरान 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' को आज मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत एक करोड़ परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। प्रत्येक घर को 1 किलोवाट प्रणाली के लिए 30,000 रुपये और 2 किलोवाट प्रणाली के लिए 60,000 रुपये की सब्सिडी मिल सकती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ सीजन 2024 के लिए पीएंडके उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी को मंजूरी दी।

तीन सेमीकंडक्टर इकाइयां स्थापित करने के प्रस्तावों को भी मंजूरी

केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल ने गुजरात और असम में 1.26 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ तीन सेमीकंडक्टर इकाइयां स्थापित करने के प्रस्तावों को भी गुरुवार को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तावों को मंजूरी देने के बाद दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सभी तीन इकाइयों का निर्माण अगले 100 दिनों के भीतर शुरू हो जाएगा। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड पावरचिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्प (ढरटउ), ताइवान के साथ साझेदारी में एक सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करेगा। इस यूनिट का निर्माण गुजरात के धोलेरा में किया जाएगा।

चालू वित्त वर्ष के पहले नौ माह में देश में एफडीआई प्रवाह में कमी, 13% घटकर 32 अरब डॉलर पर पहुंचा

एजेंसी

नई दिल्ली। देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का प्रवाह चालू वित्त वर्ष के पहले नौ माह यानी अप्रैल-दिसंबर-2023 में 13 प्रतिशत घटकर 32.03 अरब अमेरिकी डॉलर रह गया है। सरकारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली है।मुख्य रूप से कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, दूरसंचार, वाहन और फार्मा क्षेत्रों में कम निवेश के कारण एफडीआई घटा है। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में देश में 36.74 अरब डॉलर का एफडीआई आया था। हालांकि, चालू वित्त वर्ष की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के दौरान एफडीआई प्रवाह 18 प्रतिशत बढ़कर 11.6 अरब डॉलर रहा है, जो 2022-23 की समान तिमाही के दौरान 9.83 अरब डॉलर था।उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के आंकड़ों के अनुसार, कुल एफडीआई प्रवाह (जिसमें इक्विटी प्रवाह, पुनर्निवेश आय और अन्य पूंजी शामिल है।

'खाली होने पर रोहित और कोहली को भी घरेलू क्रिकेट खेलना चाहिए'

उन्होंने कहा कि सिर्फ ईशान और श्रेयस को सजा देना सही नहीं है। आजाद ने कहा- सिर्फ दो को सजा देना सही नहीं है। हर किसी को सजा मिलनी चाहिए। सभी को समान नजर से देखा जाना चाहिए।

एजेंसी

नई दिल्ली। भारत की 1983 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य कीर्ति आजाद ने बृहस्पतिवार को क्रिकेटरों के लिये रणजी ट्रॉफी खेलने के बीसीसीआई के निर्देश का समर्थन करते हुए कहा कि यह अच्छी पहल है और रोहित शर्मा तथा विराट कोहली समेत भारतीय टीम के हर सदस्य पर लागू होनी चाहिए।ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को रणजी ट्रॉफी नहीं खेलने के कारण केंद्रीय अनुबंध गंवाना पड़ा है। आजाद ने कहा- यह निर्देश बहुत अच्छी पहल है। हर किसी को रणजी ट्रॉफी खेलनी चाहिए। पांच दिन का क्रिकेट ही असली क्रिकेट है। घरेलू क्रिकेट खेलना अच्छी बात है।उन्होंने कहा- जब भी खिलाड़ी खाली हो तो उन्हें अपने प्रदेश के लिये रणजी क्रिकेट खेलना चाहिए। चाहे वह रोहित शर्मा हो या विराट कोहली। प्रदेश ने आपको खिलाड़ी बनने का मौका दिया जिससे आप देश के लिये खेल सके।हालांकि, उन्होंने कहा कि सिर्फ ईशान और श्रेयस को सजा देना सही नहीं है। आजाद ने कहा- सिर्फ दो को सजा देना सही नहीं है। हर किसी को सजा मिलनी चाहिए। सभी को समान नजर से देखा जाना चाहिए। आजाद ने इस पर टिप्पणी से इनकार कर दिया कि क्या ईशान और श्रेयस के लिये रास्ते अब बंद हो चुके हैं।उन्होंने कहा- मेरा सवाल यह है कि क्या वे पर्याप्त घरेलू क्रिकेट खेल रहे हैं। वे टी20 क्रिकेट खेल रहे हैं और हर प्रदेश में टी20 क्रिकेट लीग है। जब हम खेलते थे तब सारे सदस्य प्रदेश के लिए खेलते थे और इसमें गर्व महसूस करते थे लेकिन अब ऐसा नहीं है।

हॉकी इंडिया ने कहा- महासंघ में गुटबाजी और मतभेद नहीं

एजेंसी

नई दिल्ली। हॉकी इंडिया ने महासंघ में गुटबाजी और आपसी मतभेदों के आरोपों को खारिज कर दिया है। महासंघ के अध्यक्ष दिलीप टिर्की और महासचिव भोलानाथ सिंह ने बुधवार को एक संयुक्त बयान में कहा कि हॉकी की बेहतरी के लिए वे मिलकर काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा, ''हाल ही में कुछ निवर्तमान अधिकारियों ने मीडिया में कहा है कि हॉकी इंडिया में गुटबाजी है। यह सही नहीं है। हॉकी के हित के लिए हम एकजुट होकर काम करते रहेंगे।''13 साल बाद भारतीय हॉकी से नाता तोड़ने के बाद पूर्व सीईओ एलेना नॉर्मन ने कहा था कि हॉकी इंडिया में जिस तरह का माहौल बन गया था, उसमें काम करना मुश्किल होता जा रहा था और ऐसे में उनके पास त्यागपत्र देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था।

2024-25 सीजन के लिए 30-32 मिलियन टन गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित

एजेंसी

नई दिल्ली। 2024-25 के आगामी रबी विपणन सत्र के दौरान गेहूं खरीद का अनुमान 30-32 मिलियन टन की सीमा में तय किया गया था। गेहूं के अलावा मंत्रालय ने 90 लाख से 1 करोड़ टन के बीच रबी धान खरीद का लक्ष्य तय किया है।सरकार ने 2024-25 रबी विपणन सत्र के लिए 3 से 3.2 करोड़ टन गेहूं खरीद का एक रूढ़िवादी लक्ष्य तय किया है। खाद्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। कृषि मंत्रालय द्वारा 2023-24 फसल वर्ष (जुलाई-जून) में 11.4-11.5 करोड़ टन गेहूं के रिकॉर्ड उत्पादन की उम्मीद के बावजूद इस बार कम लक्ष्य तय किया गया है।राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार को केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्यों के खाद्य सचिवों के साथ विचार-विमर्श के बाद लक्ष्य तय किया गया। मंत्रालय ने एक बयान में

कहा, "विचार-विमर्श के बाद, 2024-25 के आगामी रबी विपणन सत्र के दौरान गेहूं खरीद का अनुमान 30-32 मिलियन टन की सीमा में तय किया गया था। गेहूं के अलावा मंत्रालय ने 90 लाख से 1 करोड़ टन के बीच रबी धान खरीद का लक्ष्य तय किया है।" सरकार ने रबी के मोटे अनाज/बाजरा (श्री अन्न) के लिए 6,00,000 टन खरीद का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। बैठक में, केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से फसलों के विविधीकरण और आहार पैटर्न में पोषण बढ़ाने के लिए बाजरा की खरीद पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा है। 2023-24 सीजन में, सरकार ने 34.15 मिलियन टन के लक्ष्य के मुकाबले लगभग 26.2 मिलियन टन गेहूं की खरीद की। 2022-23 में 44.4 मिलियन टन के लक्ष्य के मुकाबले गेहूं की खरीद केवल 18.8 मिलियन टन थी। उस दौरान उत्पादन में गिरावट के कारण खरीद कम थी।

आरसीबी के खिलाफ लौटेंगी मुंबई की कप्तान हरमनप्रीत

चोट के कारण नहीं खेल सकी थीं पिछला मैच

एजेंसी

नई दिल्ली। एडवर्डर्स ने मैच के बाद प्रेस कांफ्रेंस में कहा- हरमन चयन के लिये उपलब्ध नहीं थीं, लेकिन शनिवार को आरसीबी के खिलाफ खेलेंगी। मुझे इसका पूरा यकीन है। हरमनप्रीत ने इस डब्ल्यूपीएल में दो मैचों में 101 रन बनाए हैं।मुंबई इंडियंस के मुख्य कोच चार्लोट एडवर्डर्स ने कहा कि कप्तान हरमनप्रीत कौर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ शनिवार को डब्ल्यूपीएल के अगले मैच में उपलब्ध होंगी। फॉर्म में चल रही हरमनप्रीत चोट के कारण बुधवार को यूपी वारियर्स के खिलाफ नहीं खेल सकी थी। मुंबई को सात विकेट से पराजय का सामना करना पड़ा था।एडवर्डर्स ने मैच के बाद प्रेस कांफ्रेंस में कहा- हरमन चयन के लिये उपलब्ध नहीं थीं, लेकिन शनिवार को आरसीबी के खिलाफ खेलेंगी। मुझे इसका पूरा यकीन है। हरमनप्रीत ने इस डब्ल्यूपीएल में दो मैचों में 101 रन बनाए हैं।मुंबई को अनुभवी तेज गेंदबाज शबनम इस्माइल की कमी भी खली जो चोटिल है। एडवर्डर्स ने कहा कि उनकी फिटनेस पर नजर रखी जा रही है, लेकिन आरसीबी के खिलाफ उनका खेलना मुश्किल है। उन्होंने कहा- हम उसके लिए इंतजार कर रहे हैं। यह लंबा नहीं होना चाहिए, लेकिन हम कोई जोखिम नहीं लेना चाहते।

चुनावों में पूर्ण जन-भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे 48000 संगठनों से जुड़े नौ करोड़ कारोबारी

⇨ वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए व्यापारियों के सहयोग की पेशकश पर कैट ने गुरुवार को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को पत्र भेजा है। इसमें व्यापारी संगठनों के सक्रिय सहयोग द्वारा आगामी लोकसभा चुनावों में वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने में सहयोग देने की पेशकश की गई है...

एजेंसी

नई दिल्ली। लोकसभा चुनावों में पूर्ण जन-भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए इस बार कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) भी चुनाव आयोग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगा। कैट से जुड़े करीब 48000 व्यापारिक संगठन, जिनके साथ नौ करोड़ से अधिक छोटे-बड़े कारोबारी काम कर रहे हैं, वे लोकसभा चुनाव में अपने सक्रिय सहयोग के द्वारा वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएंगे। वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए व्यापारियों के सहयोग की पेशकश पर कैट ने गुरुवार को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को पत्र भेजा है। इसमें व्यापारी संगठनों के सक्रिय सहयोग द्वारा आगामी लोकसभा चुनावों में वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने में सहयोग देने की पेशकश की गई है।कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया एवं राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने बताया, दिल्ली में 3500 तो देश भर में लगभग 48 हजार से अधिक व्यापारी संगठन कार्य कर रहे हैं। ये संगठन, देश भर में लगभग 9 करोड़ से अधिक व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। देश के घरेलू व्यापार में लगभग 25 करोड़ लोग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार पाते हैं। इस बड़े नेटवर्क की पहुंच देश के हर हिस्से तक है। यह व्यापारिक समुदाय, देश की सामाजिक-आर्थिक संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी वजह से कैट ने चुनाव आयोग को, व्यापारियों के सहयोग का प्रस्ताव दिया है।दोनों व्यापारी नेताओं ने कहा, देश भर में व्यापारी समुदाय का एक व्यापक नेटवर्क और प्रभाव है। यह बात सभी लोग जानते हैं कि देश के 140 करोड़ लोगों की जरुरतों का प्रथम संपर्क व्यापारियों की दुकानें ही हैं। इस नाते से देश के 9 करोड़ से अधिक व्यापारियों का सीधा संपर्क देश के हर राज्य में प्रत्येक व्यक्ति से होता है।

वाल्ट डिज्नी और रिलायंस मीडिया के विलय का एलान

एजेंसी

नई दिल्ली। भारत में वाल्ट डिज्नी और रिलायंस इंडस्ट्रीज के मीडिया ऑपरेशन का विलय हो गया है। बयान के अनुसार, रिलायंस इस डील के तहत दोनों कंपनियों के विलय से बनी इकाई में 11,500 करोड़ रुपये निवेश करेगी। वॉल्ट डिज्नी कंपनी और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बुधवार को भारत में अपने मीडिया परिचालन का विलय कर 70,000 करोड़ रुपये की एक बड़ी कंपनी बनाने की घोषणा की। डिज्नी और रिलायंस इस संबंध में एक बाध्यकारी समझौते पर हस्ताक्षर करेंगी। इस कंपनी में रिलायंस की 63.16 फीसदी हिस्सेदारी होगी। वहीं डिज्नी को 36.84 फीसदी हिस्सेदारी मिलेगी। दोनों कंपनियों के मीडिया ऑपरेशन से बने संयुक्त उद्यम की चेयरपर्सन नीता अंबानी होंगी। वहीं उदय शंकर इस नई कंपनी के उपाध्यक्ष होंगे।

सौदे से भारत के सबसे बड़े मनोरंजन साम्राज्य का होगा निर्माण

रिलायंस अपनी मीडिया और एंटरटेनमेंट यूनिट वायकॉम 18 के माध्यम से कई टीवी चैनल्स, जियो स्ट्रीमिंग एप का संचालन करता है। वहीं वाल्ट डिज्नी का भारत में वेंचर डिज्नी इंडिया हैं, जिसके अंतर्गत स्टार इंडिया भी आता है। जिसके पास कलर्स, स्टार प्लस, स्टार गोल्ड, स्टार स्पोर्ट्स जैसे चैनल्स का स्वामित्व है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मीडिया ऑपरेशंस और वाल्ट डिज्नी का विलय भारत के सबसे बड़े मनोरंजन साम्राज्य में से एक का निर्माण करेगा, जिसका मुकाबला जी एंटरटेनमेंट और सोनी के संयुक्त उद्यम और नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम जैसे स्ट्रीमिंग दिग्गजों से होगा।

भारत के मीडिया क्षेत्र में आएंगे बड़े बदलाव

बयान में कहा गया है कि 'विलय से बने संयुक्त उद्यम से भारत में डिजिटल और मीडिया के क्षेत्र में बड़े बदलाव आएंगे। इससे उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता और बेहतर कंटेंट कहीं भी और कभी भी मिल सकेगा।' इस जॉइंट वेंचर (संयुक्त उद्यम) को भारत में डिज्नी फिल्म के वितरण और प्रोडक्शन के भी अधिकार मिलेंगे। विलय पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी ने कहा कि 'यह एक ऐतिहासिक समझौता है, जो भारत के मनोरंजन जगत में नए युग की शुरूआत करेगा। हम हमेशा डिज्नी की बतौर सबसे अच्छे मीडिया ग्रुप के तौर पर इज्जत करते हैं और इस संयुक्त उद्यम को लेकर रोमांचित हैं।

मैनचेस्टर सिटी ने ल्यूटन टाउन को 6-2 से रौंदा

हालैंड ने दागे पांच गोल; न्यूकैसल और लिसेस्टर भी जीता

⇨ हालैंड ने अपना पहला गोल तीसरे और दूसरा गोल 18वें मिनट में किया। उन्होंने अपनी हैट्रिक 40वें मिनट में पूरी की। इसके बाद उन्होंने तीन मिनट के अंदर दो गाल कर दिए। उन्होंने 55वें मिनट में अपना चौथा और 58वें मिनट में पांचवां गोल दागा।

एजेंसी

नई दिल्ली। स्टार स्ट्राइकर एर्लिंग हालैंड के दमदार प्रदर्शन के दम पर मैनचेस्टर सिटी ने एफए कप फुटबॉल के मुकाबले में ल्यूटन टाउन को 6-2 से करारी शिकस्त दी। इस जीत में हालैंड चमके जिन्होंने पांच गोल किए। उनके चार गोल करने में केविन डि ब्रुईन ने मदद की। हालैंड ने दूसरी बार क्लब के लिए एक मैच में पांच गोल दागे हैं।हालैंड पैर में चोट की वजह से दिसंबर से जनवरी तक खेल से दूर थे और अब इस मैच के जरिए वह पूरी तरह से स्वस्थ दिखाई दिए। माटेयो कोवाकिक (72वें मिनट) ने सिटी के लिए छठा गोल किया, जबकि जॉर्डन क्लार्क (45 और 52वें मिनट) ने ल्यूटन के लिए दो गोल किए। हालांकि, मैच में हालैंड के पास दोगनी हैट्रिक करने का मौका था, लेकिन टीम के कोच पेप गॉर्डियोला ने उन्हें 77वें मिनट में मैदान से बाहर भेज दिया और उनकी जगह स्थानापन्न खिलाड़ी जूलियन अल्वारेज को मैदान पर उतारा।हालैंड ने अपना पहला गोल तीसरे और दूसरा गोल 18वें मिनट में किया। उन्होंने अपनी हैट्रिक 40वें मिनट में पूरी की। इसके बाद उन्होंने तीन मिनट के अंदर दो गाल कर दिए। उन्होंने 55वें मिनट में अपना चौथा और 58वें मिनट में पांचवां गोल दागा।एफए कप के अन्य मुकाबलों में न्यूकैसल ने पेनाल्टी शूटआउट में ब्लैकबर्न रोवस को 4-3 से हराया। निर्धारित समय तक स्कोर 1-1 से बराबर रहा था। वहीं, लिसेस्टर सिटी ने बोर्नमाउथ को 1-0 से पराजित कर दिया। मैच का एकमात्र गोल लिसेस्टर के अब्दुल फेटेवु इस्सहाकू ने दागा।

एसबीआई का अनुमान- तीसरी तिमाही में 6.9 फीसदी रह सकती है वृद्धि दर

एजेंसी

नई दिल्ली। देश की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 6.7 से 6.9 फीसदी रह सकती है। यह दूसरी तिमाही के 7.6 फीसदी के मुकाबले कम है। वृद्धि दर में कमी की वजह कृषि क्षेत्र का खराब प्रदर्शन है। एसबीआई रिसर्च की बुधवार को जारी रिपोर्ट में दूसरी तिमाही में वृद्धि दर में तेजी का प्रमुख कारण सरकार के खर्च और विनिर्माण गतिविधियों में तेजी रही। रिपोर्ट में चौथी तिमाही में वृद्धि दर 6.8 फीसदी रहने की संभावना जताई ?गई है।?सरकार बृहस्पतिवार को जीडीपी के तीसरी तिमाही के आंकड़े जारी करेगी।?

वाणिज्यिक उधारी सितंबर तिमाही में 11 फीसदी बढ़ी

वाणिज्यिक उधारी सितंबर तिमाही में 11 फीसदी बढ़कर 28.2 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गई है। ट्रांसयूनियन सिबिल के बुधवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, कुल मूल्य में 37 फीसदी हिस्सा विनिर्माण क्षेत्र का है। 28 फीसदी हिस्सा ट्रेड का और पेशेवर सेवाओं एवं अन्य क्षेत्रों का हिस्सा 35 फीसदी है। आर्थिक गतिविधियों में तेजी से वाणिज्यिक क्षेत्रों में कर्ज मांग बढ़ी है।?पोर्टफोलियो वृद्धि और बेहतर क्रेडिट प्रदर्शन के जरिये आर्थिक विकास की संभावनाओं के कारण ऋणदाता अब छोटे उद्योगों को ज्यादा उधारी देने पर विचार कर सकते हैं।

दो साल में 20 फीसदी तक बढ़ गई मकानों की औसत कीमतें

देश के आठ प्रमुख शहरों में पिछले दो साल में मकानों की औसत कीमतें करीब 20 फीसदी तक बढ़ी हैं। क्रेडाई, कोलियर्स और लियासेस फोरास की संयुक्त रिपोर्ट के मुताबिक, मकानों की मांग बढ़ने की वजह से कीमतों में तेजी आई ?है।?रिपोर्ट के मुताबिक, बंगलूरू, दिल्ली-एनसीआर और कोलकाता में 2021 की तुलना में 2023 में सबसे ज्यादा करीब 30 फीसदी दाम बढ़े हैं। इसमें आगे कहा गया है कि मकानों की मांग, बिक्री और आपूर्ति के लिहाज से रियल एस्टेट की वर्तमान स्थिति काफी बेहतर है।

दो लाख करोड़ डॉलर का होगा खुदरा क्षेत्र

भारत का खुदरा क्षेत्र अगले दशक में 9-10 फीसदी की दर से बढ़कर दो लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच सकता है। स्थिर विकास के साथ खर्च में मजबूती बनी रहेगी। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार, संगठित खुदरा विक्रेताओं को प्रदर्शन बनाए रखने और विकास जारी रखने की जरूरत होगी।?यह क्षेत्र विकास की गति और आकार को प्रभावित करने वाले बदलावों से गुजर रहा है।

विदेशी निवेशकों को खुलासा नियमों में राहत

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कुछ विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए ज्यादा खुलासा करने से संबंधित नियमों में ढील देने का प्रस्ताव किया है। नियामक का मानना है कि इससे कारोबार करने में आसानी होगी। सेबी ने बिना प्रवर्तक समूह के इकाइयों में हिस्सा रखने वाले कोषों को भी छूट का प्रस्ताव किया है। इन पर 8 मार्च तक शेयरधारकों से सुझाव मांगे गए हैं।

पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र ने पीसीआई अध्यक्ष पद के लिए भरा नामांकन

एजेंसी

नई दिल्ली। दो बार के पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र झाझरिया ने भारतीय पैरालंपिक समिति (पीसीआई) के नौ मार्च को होने वाले चुनाव में अध्यक्ष पद के

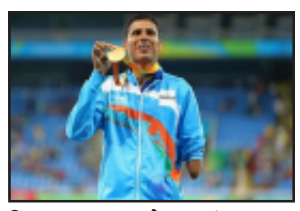

लिए बुधवार को नामांकन पत्र दाखिल किया। पीसीआई के चुनाव अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष, दो संयुक्त सचिव और कार्यकारी समिति के पांच सदस्यों के लिए होंगे।भाला फेंक के एथलीट 42 वर्षीय झाझरिया ने 2004 में एथेंस और 2016 में रियो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीते थे। उन्होंने 2021 में तोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक हासिल किया था। झाझरिया ने विश्व चैंपियनशिप 2013 में स्वर्ण पदक और 2015 में रजत पदक जीता था।

विपक्षी पार्टी ने शुरू की 'लेबर इंडियंस' पहल

आम चुनाव से पहले प्रवासी भारतीयों को साधने की कोशिश

एजेंसी

नई दिल्ली। लेबर पार्टी के विदेश मामलों के सचिव डेविड लैमी ने लंदन में संसद भवन परिसर में 'लेबर इंडियंस' पहल का शुभारंभ किया। भारत को महाशक्ति बताते हुए लैमी ने कहा कि भारत की रणनीतिक साझेदारी दलगत राजनीतिक से परे है। ब्रिटेन में इस साल के आखिर में होने वाले आम चुनाव में विपक्षी लेबर पार्टी अपनी नैया पार लगाने के लिए ब्रिटिश भारतीयों को साधने में जुट गई है। लेबर पार्टी ने प्रवासी भारतीयों से जुड़ने और सत्ता में आने के बाद एक साल में भारत के साथ बातचीत को मजबूत करने के मकसद से नया प्रवासी आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है। लेबर पार्टी के विदेश मामलों के सचिव डेविड लैमी ने लंदन में संसद भवन परिसर में 'लेबर इंडियंस' पहल का

शुभारंभ किया इस अवसर पर उन्होंने अपनी हालिया भारत यात्रा का जिक्र किया। साथ ही लैमी ने लेबर पार्टी के आगामी चुनाव में जीतने पर भारत-ब्रिटेन साझेदारी को नई ऊंचाई पर ले जाने की अपनी महत्वाकांक्षाओं को साझा किया। भारत को महाशक्ति बताते हुए लैमी ने कहा कि भारत की रणनीतिक साझेदारी दलगत राजनीतिक से परे है। उन्होंने कहा, उद्यमशीलता, इनोवेशन, वैज्ञानिक, औद्योगिक आधार और बड़ी आबादी के साथ एक महाशक्ति है।लैमी ने कहा, हालांकि भारत के सामने अभी भी चुनौतियां हैं। लेकिन मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस भू-राजनीतिक समय में ब्रिटेन को यह समझना बेहद महत्वपूर्ण है कि भारत दुनिया की एक महाशक्ति है। उन्होंने आगे कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन हैं, क्योंकि रणनीतिक रूप से दोनों देशों के बीच बहुत मजबूत संबंध हैं।

जेरेमी कॉर्बिन के कार्यकाल में भारत विरोधी टिप्पणी पर सफाई....

पूर्व लेबर नेता जेरेमी कॉर्बिन के नेतृत्व में पार्टी से जुड़ी कुछ भारत विरोधी बयानबाजी के बारे में पूछे जाने पर लैमी ने कहा कि लेबर पार्टी ने नई यात्रा शुरू की है और कीर स्टार्मर के नेतृत्व में पार्टी ने अपनी नीतियों में बदलाव किया है। उन्होंने कहा कि हमारी यात्रा स्पष्ट है। हम कॉर्बिन के वर्षों के कार्यकाल को राजनीतिक रूप से पार्टी के लिए असफल मानते हैं। मुझे लगता है कि कॉर्बिन के कार्यकाल में भारतीय समुदाय के बीच पार्टी को लेकर ऐसी धारणा बनी थी। लेकिन उनकी भारत यात्रा इस धारणा से हटकर देखने को लेकर थी।

पाकिस्तान नेशनल असेंबली का पहला सत्र शुरू

कार्यवाहक सरकार से विवाद के बीच मिली राष्ट्रपति से मंजूरी

नवनिर्वाचित संसद इसका आयोजन करेगी। दरअसल, पूरा मामला पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान की पार्टी समर्थित उम्मीदवारों को आरक्षित सीटें आवंटित करने से जुड़ा था। इसके चलते राष्ट्रपति डॉ आरिफ अल्वी का कार्यवाहक सरकार के साथ मतभेद चल रहा था।

एजेंसी

नई दिल्ली। पाकिस्तान की नवनिर्वाचित संसद ने गुरुवार को अपना पहला सत्र शुरू कर दिया है। कार्यवाहक सरकार के साथ चल रहे मतभेदों के बाद राष्ट्रपति डॉ. आरिफ अल्वी ने आखिरकार विधानसभा सत्र बुलाया है। दोनों के बीच पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी समर्थित उम्मीदवारों को आरक्षित सीटें आवंटित किए जाने के मुद्दे को लेकर विवाद चल रहा था। पिछली संसद के निवर्तमान अध्यक्ष राजा परवेज अशरफ की अध्यक्षता में उद्घाटन सत्र एक घंटे से अधिक की देरी के बाद शुरू हुआ।

पोस्ट में कही ये बात

एक्स अकाउंट पर जारी बयान में कहा गया, 'कुछ आपत्तियों के अधीन, राष्ट्रपति डॉ. आरिफ अल्वी ने इस्लामिक गणराज्य पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 54(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 29 फरवरी को नेशनल असेंबली बुलायी है।'बता दें कि कि राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 91 (2) में दी गई समयसीमा के जनादेश और निहितार्थों को ध्यान में रखते हुए और कुछ आरक्षणों के अधीन और 21वें दिन से पहले आरक्षित सीटों के मुद्दे के समाधान की उम्मीद करते हुए अपनी मंजूरी दे दी। गौरतलब है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने मंगलवार को अल्वी द्वारा उठाई गई आपत्तियों को सीरे से खारिज कर दिया था। साथ ही कहा कि पाकिस्तान के संविधान के मुताबिक, नेशनल असेंबली सत्र चुनाव के 21 दिनों के भीतर होना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 91 के तहत, नेशनल असेंबली के पहले सत्र की जरूरी तारीख 29 फरवरी है।

अल्वी के खिलाफ दो मामले करेंगे दर्ज- बिलावल

इस मीडिया रिपोर्ट में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने मगंलवार को कहा कि संविधान की अवज्ञा करने पर अल्वी के खिलाफ कई कानूनी कार्रवाई की जाएंगी।

फ्रांसीसी सांसद ने गर्भपात के अधिकारों को मंजूरी देने के लिए किया वोट

प्रधानमंत्री बोले-प्रगति की ओर बड़ा कदम

एजेंसी

नई दिल्ली। संविधान में गर्वपात के अधिकारों को मंजूरी देने के लिए पेश किए गए प्रस्ताव का उद्देश्य फ्रांसीसी कानूनी ढांचे के भीतर गर्भपात के अधिकारों को मजबूत करना है। गर्वपात फ्रांस में 1975 से ही वैध है और गर्भावस्था के पहले 10 हफ्तों में इसे वैध बताया था।फ्रांसीसी सांसद ने बुधवार को संविधान में गर्वपात के अधिकारों को मंजूरी देने के लिए मतदान किया। उन्होंने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा रो वी वेड के फैसले को पलटने के बाद इसके पक्ष में निर्णायक रूप से मतदान किया। सांसद के पक्ष में 267 और विपक्ष में 50 वोट पड़े। यह विधायी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री गेब्रियल अटाल ने इसे प्रगति की ओर एक बड़ा कदम बताया। उन्होंने महिलाओं के अपने शरीर पर स्वतंत्र रूप से नियंत्रण रखने के महत्व को दशार्या। पीएम अटाल ने कहा कि लैंगिक समानता की दिखा में एक कदम आगे बढ़ाया गया है संविधान में गर्वपात के अधिकारों को मंजूरी देने के लिए पेश किए गए प्रस्ताव का उद्देश्य फ्रांसीसी कानूनी ढांचे के भीतर गर्भपात के अधिकारों को मजबूत करना है। गर्वपात फ्रांस में 1975 से ही वैध है और गर्भावस्था के पहले 10 हफ्तों में इसे वैध बताया था। हालांकि, बाद में इसे बढ़ाकर 14 हफ्ते किया गया था। इस प्रक्रिया की लागत राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा प्रणाली द्वारा कवर किया जाएगा।यह निर्णय तब लिया गया जब नेशनल असेंबली ने नवंबर 2022 में बदलाव का समर्थन किया था।

अमेरिका बोला...

उम्मीद है भारत की अध्यक्षता में क्वाड की गति बरकरार रहेगी

व्हाइट हाइट की प्रेस सचिव कैरिन जीन पियरे ने ब्रीफिंग में कहा कि क्वाड ने पिछले तीन वर्षों में जो सफलता हासिल की है, इससे राष्ट्रपति जो बाइडन काफी खुश हैं। हमें उम्मीद है कि भारत की मेजबानी में भी यह सफलता कायम रहेगी।

एजेंसी

नई दिल्ली। भारत 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिसे लेकर अमेरिका काफी उत्साहित है। व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार शाम एक प्रेस ब्रीफिंग में इस पर बात की। व्हाइट हाइट की प्रेस सचिव कैरिन जीन पियरे ने ब्रीफिंग में कहा कि क्वाड ने पिछले तीन वर्षों में जो सफलता हासिल की है, इससे राष्ट्रपति जो बाइडन काफी खुश हैं। हमें उम्मीद है कि भारत की अध्यक्षता में भी यह गति बरकरार रहेगी। क्वाड की सफलता सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बारे में है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र स्वतंत्र हों, खुले हों और समृद्ध हों यही क्वाड का साझा दृष्टिकोण है। पियरे ने कहा कि क्वाड इंडो पैसिफिक क्षेत्र को लाभ पहुंचा रहा है। इसलिए 2024 में भी हम इस प्रगति को जारी रखना चाहते हैं।पियरे ने 12व2 पर भी बात की। ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडन 12व2 को लेकर प्रतिबद्ध हैं। 12व2 का उद्देश्य विज्ञान आधारित समाधानों को आगे बढ़ाना है। साथ ही ऊर्जा सुरक्षा, अंतरिक्ष संचालन, जल संरक्षण सहित विभिन्न क्षेत्रों की चुनौतियों का सामाधन करना है।

मॉरिशस में उद्घाटन पर बोले पीएम मोदी

'विकास साझेदारी हमारे संबंधों का प्रमुख स्तंभ'

एजेंसी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मॉरीशस समकक्ष प्रविंद जुगनाथ ने गुरुवार को मॉरीशस के अगालेगा द्वीप पर छह सामुदायिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसके साथ ही नई हवाई पट्टी(एयरस्ट्रिप) और सेंट जेम्स जेट्टी का भी संयुक्त रूप से लोकार्पण किया। पीएम कार्यालय के एक बयान के अनुसार, यह कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया था। इन कई परियोजनाओं का उद्घाटन दोनों देशों, भारत और मॉरीशस के बीच मजबूत और दशकों पुरानी विकास साझेदारी का प्रमाण है।

भारत-मॉरिशस ने रिश्ते में नई ऊंचाइयां हासिल की हैं: पीएम मोदी

इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, 'पिछले 10 वर्षों में, भारत-मॉरीशस संबंधों को अभूतपूर्व दिशा मिली है। हमने इस रिश्ते में नई ऊंचाइयां हासिल कीं। हमने वैज्ञानिक और ऐतिहासिक संबंधों को एक नया रूप दिया। विकास साझेदारी हमारे संबंधों का प्रमुख स्तंभ रही है। भारत ने हमेशा मॉरीशस की जरूरतों का सम्मान किया है'।आधिकारिक बयान के अनुसार, ये परियोजनाएं मुख्य भूमि मॉरीशस और अगालेगा के बीच बेहतर कनेक्टिविटी की मांग को पूरा करने में मदद करेंगी। पीएमओ के अनुसार इससे समुद्री सुरक्षा मजबूत होगी और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

यूएसआईएसपीएफ के अध्यक्ष ने की पीएम मोदी की सराहना

'वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नेता और मैं उनका फैन हूं'

एजेंसी

नई दिल्ली। यूएस-इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम के अध्यक्ष जॉन चेंबर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की। उन्होंने पीएम मोदी को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नेता बताया है। पूर्व टेक दिग्गज चेंबर्स ने बताया कि भारत में प्रधानमंत्री मोदी की अप्रूवल रेटिंग 76 फीसदी है, यानी की लोग उन्हें पसंद करते हैं। चेंबर्स ने उनकी (पीएम मोदी) लोगों का विश्वास बनाने की क्षमता पर भी प्रकाश डाला।जॉन चेंबर्स ने कहा, "मैं पीएम मोदी का बहुत बड़ा फैन हूं। मुझे लगता है कि वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नेता हैं। मेरी इच्छा है कि हमारे पास अमेरिका में भी ऐसे एक व्यक्ति हों। हमारे पास कोई भी ऐसा राजनीतिक नेता नहीं है,

जिन्हें 50 फीसदी अप्रूवल रेटिंग मिली हो। वहीं पीएम मोदी को 75 फीसदी अप्रूवल रेटिंग मिलीं है।"

पीएम मोदी की सराहना की

चेंबर्स ने लोगों का विश्वास हासिल करने की पीएम मोदी की क्षमता का हवाला देते हुए अमेरिकी नेताओं के साथ अच्छे रिश्ते बनाने के लिए उनकी सराहना की। उन्होंने कहा, "अगर आप नेता के बारे में सोचते हैं तो यह उनके ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में है। यह उनके रिश्तों और भरोसे के बारे में है। उन्होंने हमारे सभी राजनीतिक नेताओं के साथ अच्छे रिश्ते बनाए हैं। लोग उनपर भरोसा करते हैं।"साल 2022 में भारत और अमेरिका ने अपने द्विपक्षीय संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाई। दोनों राष्ट्र वैश्विक राजनीतिक साझेदारी का आनंद ले रहे हैं जो मानव प्रयास के लगभग सभी क्षेत्रों को कवर करती है। यह लोकतांत्रिक मूल्यों और विभिन्न मुद्दों और लोगों से लोगों के संपर्क से प्रेरित है।

भारत-अमेरिका ने रणनीतिक रोडमैप तैयार किया: मुकेश आग्ही

इससे पहले दिसंबर में यूएसआईएसपीएफ अध्यक्ष और सीईओ मुकेश आग्ही ने कहा, "पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडन की यात्राओं के दौरान कूटनीतिक गति ने एक मजबूत रणनीतिक रोडमैप तैयार किया। स्वच्छ ऊर्जा सहयोग, शिक्षा, अंतरिक्ष सहयोग, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, ड्रोन प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में नई पहल की गई।

भारतीय-अमेरिकियों को लेकर बोला व्हाइट हाउस

'H-1B वीजा प्रक्रिया में सुधार के लिए कर रहे हरसंभव प्रयास'

एजेंसी

नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ल-1इ वीजा प्रक्रिया, ग्रीन कार्ड बैकलॉग और आव्रजन प्रणाली से जुड़े अन्य मुद्दों में सुधार के लिए हरसंभव प्रयास कर रहे हैं। व्हाइट हाउस ने बुधवार को यह बात कही।

ल-1इ वीजा क्या है?

H-1B वीजा एक गैर-प्रवासी वीजा है। यह आमतौर पर उन लोगों को दिया जाता है, जो अमेरिका में काम करने के लिए जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ल-1इ वीजा ऐसे कुशल कर्मचारियों को रखने के लिए दिया जाता है, जिनके काम की जरूरत अमेरिका की कंपनियों को है। इसके बाद ग्रीन कार्ड दिया जाता है। इस वीजा की वैधता छह साल की होती है। भारतीय आईटी पेशेवर इस वीजा को सबसे ज्यादा हासिल करते हैं।

भारतीय-अमेरिकियों को लेकर पूछा गया था सवाल

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरिन जीन पीयरे ने बुधवार को एक दैनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, हमने ल-1इ वीजा, ग्रीन कार्ड बैकलॉग प्रक्रिया में सुधार के लिए कदम उठाए हैं। दरअसल, उनसे भारतीय मूल के अमेरिकी लोगों के एक वर्ग में फैली इस भावना के बारे में पूछा गया था कि राष्ट्रपति बाइडन वैध प्रवासियों की मुश्किलों को दूर करने के लिए उतने प्रयास नहीं कर रहे हैं, जितना वह अवैध प्रवासियों के लिए कर रहे हैं।

व्हाइट हाउस ने कही ये बात

पीयरे ने आगे कहा, उदाहरण के तौर पर अमेरिकी होमलैंड सुरक्षा विभाग (डीएचएस) ने पिछले महीने ही ल-1इ वीजा से जुड़े नए नियम प्रकाशित किए हैं। यह बदलाव आव्रजन प्रणाली की अखंडता को मजबूत करने और धोखाधड़ी की संभावनाओं को कम करने के लिए किए गए हैं। यह बदलाव निष्पक्ष और ज्यादा न्यायसंगत परिणामों को बढ़ावा दे रहे हैं।

इलिनॉय राज्य के प्राथमिक चुनाव के लिए भी अयोग्य घोषित

एजेंसी

नई दिल्ली। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बुधवार को कैपिटल हिल हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। शीर्ष अदालत उनकी दलीलों को सुनने पर सहमत हुआ। वहीं दूसरी ओर, इसी मामले को लेकर इलिनॉय राज्य में एक स्थानीय अदालत से उन्हें झटका लगा। अदालत ने ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव के लिए होने वाले प्राथमिक मतदान से बाहर करने का आदेश दिया है। इससे पहले मेन और कोलाराडो राज्य भी ट्रंप को राज्य के प्राथमिक मतदान के लिए अयोग्य घोषित कर चुके हैं। इलिनॉय में 19 मार्च को प्राथमिक चुनाव होंगे। न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने एक विद्रोह में भाग लिया था। इसलिए उन्हें राज्य के मतपत्र में रहने की अनुमति नहीं है। छह जनवरी 2021 को कैपिटल हिल की हिंसा में ट्रंप की भूमिका को लेकर उन्हें इलिनॉय में प्राथमिक चुनाव से बाहर किया गया।

चीनी राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो: 2023 में चीन की जीडीपी वृद्धि दर 5.2% रही

एजेंसी

बीजिंग। चीनी राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो ने '2023 में चीन के राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक विकास का सांख्यिकीय बुलेटिन' जारी किया। प्रारंभिक गणना के अनुसार, साल 2023 में वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी)1,260.582 खरब युआन था, जिसमें वर्ष 2022 की तुलना में 5.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। उनमें से प्राथमिक उद्योग का अतिरिक्त मूल्य 89.755 खरब युआन था, जो वर्ष 2022 से 4.1 प्रतिशत की वृद्धि थी, द्वितीयक उद्योग का अतिरिक्त मूल्य 482.589 खरब युआन था, जो 4.7 प्रतिशत की वृद्धि थी, तृतीयक उद्योग का अतिरिक्त मूल्य 688.238 खरब युआन था, जो 5.8 प्रतिशत की वृद्धि थी। अंतिम उपभोग व्यय ने जीडीपी की वृद्धि को 4.3 प्रतिशत अंक तक बढ़ा दिया। तिमाहियों पर नजर डालें, तो साल 2022 की चार तिमाहियों की तुलना में गत वर्ष पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 4.5 प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 6.3 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 4.9 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 5.2 प्रतिशत बढ़ी। आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2023 में, वार्षिक प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद 89,358 युआन था, जो वर्ष 2022 की तुलना में 5.4 प्रतिशत की वृद्धि थी। सकल राष्ट्रीय आय 1251.297 खरब युआन थी, जो वर्ष 2022 की तुलना में 5.6 प्रतिशत अधिक थी। देश में कुल श्रम उत्पादकता 161,615 युआन/व्यक्ति थी, जो साल 2022 की तुलना में 5.7 प्रतिशत की वृद्धि थी।

दोषी को जहरीला इंजेक्शन लगाने के लिए नस नहीं ढूंढ पाई मेडिकल टीम

एजेंसी

नई दिल्ली। अधिकारियों ने बताया कि 73 वर्षीय दोषी थॉमस क्रीच को एक घंटे के लिए मौत की सजा दी जाने वाली कक्ष में मेज पर बांधकर रखा गया था। मेडिकल की टीम सुई डालने के लिए बार बार उसके नस को ढूंढने का प्रयास कर रही थी।इडाहो में एक सीरियल कीलर को मौत की सजा देने के दौरान एक अजीबोगरीब घटना घटी। दरअसल, मेडिकल की एक टीम दोषी को इंजेक्शन देने से पहले सुई लगाने के लिए नस ही नहीं ढूंढ पाई, जिसके बाद उसकी सजा को रोक दी गई।

मेडिकल टीम की असफल प्रयासों के बाद रोकी गई सजा

अधिकारियों ने बताया कि 73 वर्षीय दोषी थॉमस क्रीच को एक घंटे के लिए मौत की सजा दी जाने वाली कक्ष में मेज पर बांधकर

रखा गया था। मेडिकल की टीम सुई डालने के लिए बार बार उसके नस को ढूंढने का प्रयास कर रही थी। इडाहो सुधार विभाग (आईडीओसी) के निदेशक जोश तेवाल्ट ने बताया कि दोषी के हाथों और पैर में आईवी लाइन खींचने के लिए आठ बार प्रयास के बाद मौत की सजा को रोक दिया गया।तेवाल्ट ने आगे कहा, "अब हमें समय सीमा और अगले कदम के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये ऐसी चीजें हैं जिसपर बाद में चर्चा होगी।" स्थानीय पत्रकार ब्रेंडा रॉडरिग्स ने बताया कि दोषी को इस दौरान कोई दर्द नहीं हुआ, लेकिन बार-बार प्रयासों के बाद उसने एक समय मेडिकल कर्मचारी को बताया कि उसके पैर में थोड़ा दर्द हो रहा है। उन्होंने आगे कहा, "लगातार प्रयासों में असफलता के बाद मौत की सजा को रोक दी गई। सजा रोकने के दौरान दोषी ऊपर की तरफ देख रहा था। वह कुछ कह रहा था, जिसे मैं सुन नहीं पाई।"

कंचन उजाला
स्वामी नमोकंचन कार्पोरेट सर्विसेस (एल.एल.पी) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक कंचन सोलंकी द्वारा उमाकान्ती ऑफसेट प्रेस, ग्राम डेहवा पोस्ट मोहनलाल गंज लखनऊ से मुद्रित एंव 61/18 चुटकी भण्डार हुसैनगंज लखनऊ से प्रकाशित।
सम्पादक
कंचन सोलंकी
RNI No:UPHIN/2019/79194
Mob
8896925119,7786893588
Email
kanchansolanki397@gmail.com
नोट : समाचार पत्र में प्रकाशित समाचारों एवं लेखों से संपादक का सहमत होना अनिवार्य नही। समस्त विवादो का निस्तारण लखनऊ न्यायालय के अधीन होगा।